साप्ताहिक

पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

# समय माया

R.N.I. No.: MP/HIN/2006/20685

प्रधान संपादक- अजमेरा एस.पी. कुमार
B.COM., M.A., LLB, CAIIB, DLLLW&PM

Webite: www.samaymaya.com
Email: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com

Cell: +91 9425125569
+91 9479535569

(C) All Copyrights reserved with chief editor, do not publish any matter without prior written permission

In case of any dispute, may be solved only in Indore Court Jurisdiction

वर्ष 18 | अंक 03 | प्रति सोमवार इंदौर, 19 अगस्त से 25 अगस्त 2024 | पृष्ठ 8 | मूल्य 5/- रुपए

# मोदी, माधुरी बुच, अडानी बंधु का गठजोड़

## हिंडेनबर्ग की रिपोर्ट चारों के दस्तावेजों का ही सच

### देश व जनता को स्टाक मार्केट से लूटने के षड़यंत्रों का सच, नकार के भी नहीं नकारे जा सकते

2014 से देशकी सत्ता संभालने के बाद मोदी ने हर कदम पूरे देश देश के कानून देश की सत्ता को अपने बाप की जागीर समझ मूढ़ ने मोटी कमाई के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अपने-अपने मित्रों के लिए हर प्रकार के षडयंत्र किये जो रह रहकर 2014 से ही सामने आने लगे थे। भारत में कितना भी झूठ बोला जाए और उसे झूठ को और राष्ट्रीय शैतान संघ और भूखेड़ा जन पार्टी के लोग सही सिद्ध करने की कोशिश करें परंतु 2-5% सच सामने आ ही जाता है। वह भी पूरे देश और दुनिया को हिला देता है। इस संबंध में स्टॉक मार्केट की सेबी मुखिया माधवी बुच पहले सदस्य बनाई जाती है। और फिर पूर्णकालिक अध्यक्ष बना खुलकर अपने मित्रों अडानी अंबानी टाटा बिरला आदि के शेयर्स को उच्च स्तर पर पहुंचाने के लिए देश के वित्तीय संस्थानों से लेकर सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के लाखों करोड़ों के सरकारी उपक्रमों के लाभ के नाम से लेकर पेंशन फंड तक को भी झोंक दिया जाकर मित्रोंके शेयर्स उच्च स्तर पर बनाए रखे जाते हैं।

यह कोई 18 महीने होने जा रहा है जब अडानी समूह पर हमारी ओरिजनल रिपोर्ट ने फुल प्रूफ सबूत पेश किया था जिसमें कहा गया था कि भारतीय उद्योगपति समूह कारपोरेट इतिहास में सबसे बड़े घोटाले का संचालन कर रहा है। हमारी रिपोर्ट ने बताया था कि ढेर सारी आफशोर कंपनियां हैं जिनमें ज्यादातर प्राथमिक तौर पर मारीशस आधारित शेल कंपनियां हैं, उनको लाखों-करोड़ों डालर गुप्त लेन-देन, अघोषित निवेश और स्टॉक मैनिपुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।

उसके बाद हमारे ओरिजनल के साथ 40 से ज्यादा स्वतंत्र मीडिया इन्वेस्टिगेशन और उनके द्वारा पेश किए गए सबूतों के बावजूद भारतीय सिक्योरिटी रेगुलेटर सेबी ने अडानी समूह के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बड़े और इतने भीषण मुद्दे के बावजूद सेबी ने इसे तकनीकी उल्लंघन बताकर अडानी समूह के खिलाफ केवल सांकेतिक कार्रवाई की। इसकी बजाय उल्टे सेबी ने 27 जून, 2024 को हम लोगों को नोटिस भेज दिया। सेबी ने 106 पेज के हमारे विश्लेषण में कोई तथ्यात्मक गलती होने का आरोप नहीं लगाया। इसकी बजाय हम पर पूरी जानकारी न देने के इर्द-गिर्द अपने आरोपों को केंद्रित किया- जिसे पहले ही हमने सार्वजनिक कर दिया था- और इस बात पर लगातार बहस करते रहे कि हमें और पुख्ता सबूत मुहैया कराने चाहिए थे।

सेबी की नोटिस ने यह भी दावा किया कि हमारी रिपोर्ट लापरवाही भरी है क्योंकि इसने एक प्रतिबंधित ब्रोकर के हवाले से जिसे सेबी से डील करने का एक विशेष क्षेत्र का ही अनुभव है, यह बताया था कि कैसे रेगुलेटर को उन जटिल आफशोर कंपनियों की जानकारी थी जिसे अडानी समूह नियमों को तोड़ मरोड़कर इस्तेमाल करता था। और यह कि रेगुलेटर पूरी योजना में शामिल था।

जुलाई, 2024 की कारण बताओ नोटिस के अपने जवाब में हमने लिखा कि हमने यह अजीब पाया कि कैसे सेबी- एक रेगुलेटर जिसे विशेष तौर पर फ्राड गतिविधियों को रोकने के लिए बनाया गया है- ने उन पार्टियों में जो पब्लिक कंपनियों के जरिये आफशोर शेल कंपनियों के साथ लाखों-करोड़ों डालर के अघोषित लेन-देन को संचालित कर रही हैं, बहुत कम रुचि दिखायी। और इस तरह से अपने स्टॉक को निवेश वाले नकली निकायों के नेटवर्क के जरिये बढ़ा रही है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसा कि कोर्ट के रिकॉर्ड में पूरा विवरण है उसके मुताबिक इन शेयरधारकों के निवेश की जांच में सेबी का हाथ बिल्कुल खाली रहा। जून 2024 के आखिरी सप्ताह में अडानी के सीएफओ जुगशिंदर सिंह ने बताया कि अडानी समूह को सेबी की तरफ से मिली कुछ नोटिसें मामूली किस्म की हैं। इसके साथ ही उनकी गंभीरता को भी अभी प्रक्रिया पूरी होती उससे पहले ही समाप्त कर दिया गया।

जैसा कि हमारे ओरिजनल अडानी रिपोर्ट में डीआरआई के दस्तावेज के हवाले से यह आरोप लगाया गया था कि अडानी समूह ने ऑफशोर शेल कंपनियों का इस्तेमाल कर भारतीय लोगों से मनी लांडर कर मुख्य बिजली के संयंत्रों के आयात में अनुमान से ज्यादा ऊंची कीमतें लगायीं।

उसी समय गैर लाभकारी प्रोजेक्ट 'अडानी वाच' द्वारा दिसंबर 2023 में की गयी एक दूसरी जांच ने यह दिखाया कि गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी द्वारा नियंत्रित की गयी शेल कंपनियों का एक पूरा जाल कैसे बिजली के इन ऊंची कीमतों वाले फंड को कथित तौर पर हासिल किया।

(शेष पेज 2 पर)

## भारतीय रेलः लूट, बेचने की चल रही धक्कम पेल

# जनता से हर कदम लूट, दुर्घटनाओं से मौत का तांडव

### हर तरफ हर तरह से तबाही मचाई मोदी ने पूरे रेलवे में, 3 साल के बाद भी हजारों यात्री ट्रेन बंद, 3ˇ किराया, सुविधाहीन, दुर्घटनायें करवा, कुकर्मों को छुपाने का षड्यंत्र

मोदी ने देश में सत्ता संभालने के बाद चारों तरफ लूट डकैती और बर्बादी का तांडव रच दिया। देश की सबसे बड़ी संस्थान भारतीय रेलवे को जहां पर शुरुआत में बचपन में गुजरात के बड़नगर के रेलवे प्लेटफार्म पर चाय बेचने की बात किया करता था। मोदी का जन्म 1950 में हुआ और बड़नगर में 1971 के बाद रेलवे प्लेटफार्म बना। तो मोदी के बचपन में कहां चाय बेची? वह रेलवे से अत्यधिक लगाव होने की बात करता है और उसे लगाओ का परिणाम है कि चारों तरफ न केवल बंदे भारत यात्री ट्रेन पूरी अडानी के नाम है। आने को प्लेटफार्म से लेकर आने को रेलवे लाइन भी उसने अडानी के नामकर दी या अन्य लोगों को रेलवे प्लेटफार्म 30 से 50 साल के पट्टे पर बेंचे। जहां अब गाड़ी की पार्किंग के 50 रुपए लिए

जाते हैं और प्लेटफार्म के भी रू. 25 वसूले जाते हैं जहां तक अन्य यात्री ट्रेनों का सवाल था तो उसमें भी इस जलशा ने चारों तरफ लूट का तांडव छुआ दिया एक तरफ कोरोना की आड़ में पूरे के पूरे रेलवे को ध्वस्त करने और बेंचने का षड़यंत्र किया गया ज्यादा हल्ला मचा। तू शस्त्र सुरक्षा के नाम पर कुछ ट्रेन दो से तीन गुना किराए पर चालू कर दी गई। पर सारी 5000 से ज्यादा पैसेंजर ट्रेन जो थी पूरे भारत की जिन में गरीब मजदूर किसान आदि यात्रा करते थे उन सबको पूरी तरह से बंद कर दिया गया ताकि लोगों को मजबूरी में यात्रा करने पर उन्हें ट्रेने खाली जाने के बाद में भी जानबूझकर एसी कोच में बुकिंग करवाने के लिए मजबूर कर दिया इस जालसाज डकैत ने, उसमें भी फ्लेक्सी कराया कर दिया हवाई जहाज की तरफ जैसे-जैसे सेट कम होती जाएगी वैसे-वैसे वसूली बढ़ती जाएगी और ऑनलाइन के पाखंड के नाम परयदि यात्री स्वयं सीधे टिकट बुक करना चाहता था तो उससे वह टिकट ऑनलाइन आज भी बुक नहीं होता वहां पर हमेशा वेटिंग दिखाई जाती है और वही टिकट जब रु. 100-200 ज्यादा देकर गुजराती दलालों के उप दलालों के साइबर सेंटर के माध्यम से बुक करवाए जाते हैं तो तत्काल बुक हो जाते हैं दूसरी तरफ जब सारी पैसेंजर ट्रेन बंद कर दी गई तो स्वाभाविक सी बात थी एक्सप्रेस के नाम पर और आरक्षण वाले सेकंड क्लास के डब्बे खाली होने पर भी उनमें बुकिंग नहीं मिलती थी तो मजबूरी में लोगों को ऐसी प्रथम दुखी कृति में बुकिंग करवानी पड़ती थी और आज भी यही हाल है (शेष पेज 7 पर)

साप्ताहिक समय माया

## संपादकीय

# सत्ता के कर्मों की शर्मिंदगी

**जब सत्ता में मूड आपराधिक शासक होगा। तो स्वाभाविक है, न केवल देश की जनता व्यवसाय रोजगार उद्योगकी बर्बादी तो निश्चित है हीजिसे हम देख ही रहे हैं 10 साल से। पर वह आपराधिक मूढ़ शासक अपने अहंकार को पूरा करने किसी भी हद तक न केवल देश में वरन विश्व क्षितिज पर भी देश को देश की जनता को गिरा नीचा दिखा सकता है। और अपनी अहं की संतुष्टि के साथ अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शन करने में कहीं झुकता नहीं वही हाल ओलंपिक में हमारे देश की बेटी .विनेश फोगाट के साथ हुआ। दिस इस जालसाजी से जानबूझकरस्वर्ण पदकना मिल जाए क्योंकि उसने उसके साथ मेंदेश की राजधानी के रामलीला मैदान परउसको घसीटवाया था जलील किया थाअगर उसे स्वर्ण पदक मिल जाएगातो यह और जलील होगा इसलिए अहं की संतुष्टिके लिए जानबूझकर 100 ग्राम वजन बढ़वाने का बहाना लेकर पदक से पेरिस के ओलंपिक में वंचित करवाया गया। भले ही अंतरराष्ट्रीय स्तर परहम पदक से वंचित हो गए प्रदेश की जनता नेजिस तरह से उसके लौटने पर विनेश फोगाट का स्वागत किया। उससे अहंकारी राजा व उसके गिरोह के दुष्कर्मियों को काफी मानसिक कष्ट तो पहुंचा ही देश की जनता को बहुत कष्ट हुआ कि ओलंपिक में हम लोग कुछ खास नहीं कर सके, खासकर फेंकने के मामले में। पूरा विश्व हमारी तरफ हसरत भरी निगाहों से देख रहा था, पर हम स्थिर विकास की तरह एक दुःस्वप्न बन कर रह गए। और कोई प्रतियोगिता हो तो चलो गम खा लें लेकिन फेंकने के मामले में... नहीं-नहीं! इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कम से कम फेंकने के मामले में हम इतने बेगैरत कैसे हो सकते हैं? जिस पहचान के लिए हम जाने जाते हैं, हम उसी के प्रति इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? हम अनजाने में ही सही, अपनी अस्मिता से खिलवाड़ कर रहे हैं। ध्यान रहे, यहां हम भाला-वाला फेकने की बात नहीं कर रहे हैं। भाई हम ठहरे पक्के गांधीवादी। अहिंसा से हमारा बहुत गहरा किताबी रिश्ता रहा है। बताते हैं कि अहिंसा कमजोरों की ताकत रही है, सो जब तक हम कमजोर रहते हैं, इसको सीने से चिपकाए रहते हैं, पर जैसे ही मजबूत होते हैं, अपरिग्रह सिद्धांत के तहत हम तत्काल अहिंसा को पालनार्थ दूसरे कमजोरों को सौंप देते हैं। इसलिए यहां भाला की बात कतई नहीं। यह एक हिंसक खेल है। और फिर हम भाला फेंके ही क्यों? जो काम हम मुंह से कर सकते हैं, उसके लिए भाले-वाले की जरूरत भी क्या? खामखां ऊर्जा क्षय करने की क्या जरूरत? भाई जब पहले से ही हम ऊर्जा के मामले दूसरे देशों का मुंह तकते रहते हैं, ऐसे में बची-खुची अपनी ऊर्जा को भाला फेंकने में व्यय करना, क्या यूं ही उचित होगा? आप ही बताइए! हमने कई बार, कई मौकों पर, बल्कि बेमौकों पर भी खूब फेंका है, बेधड़क फेंका है। अपने यहां की छोड़िए, हम तो दूसरों के यहां भी (मने दूसरी देशों में) खुलकर फेंकते हैं। बल्कि वहां तो और खुलकर फेंकते हैं। ऐसी ही एक अंतरराष्ट्रीय फेंक हमने गत वर्ष फेंकी थी, जब बतौर मेहमान एक देश में हमने हर मिनट में एक स्कूल, हर घंटे में एक कॉलेज, हर दूसरे- तीसरे दिन एक यूनिवर्सिटी और हर सप्ताह एक नया आईआईएम या आईआईटी खोलने की फेंक आए थे। यह तो एक छोटी सी नजीर दी हमने। बाकी अपन का इतिहास तो न जाने ऐसी कितनी ऊंची और लंबी फेंकों से भरा हुआ है। कुल मिलाकर गौरवशाली इतिहास कहा जा सकता है अपना। इसलिए हम फिर कहते हैं कि फेंकने में हमारा कोई सानी नहीं। लेकिन ओलंपिक ने हमें शर्मसार किया। हम मुंह छुपाते घूम रहे हैं। हमें आत्मपरीक्षण करना चाइए। निःसंदेह समस्या हमारे प्रतियोगियों में नहीं, समस्या चयन में है। समस्या प्रतिभाओं के चयन में हैं। अगर सही प्रतिभा का चयन किया होता तो क्या ये दशा होती। हमारी भूमि अभी फेंकने वालों से शून्य नहीं हुई है। बल्कि हमें अपनी उर्वरा भूमि पर नाज़ है। बस चयन में थोड़ी सावधानी बरतिये। कामयाबी पैरों में न लोटे तो हमसे कहिए।**

# मोदी, माधुरी बुच, अडानी बंधु का गठजोड़

**पेज 1 का शेष**

एक जटिल ढांचे में बरमूडा आधारित ब्रिटिश ओवरसीज क्षेत्र और टैक्स हैवेन में स्थित ग्लोबल डायनमिक अपार्च्यूनिटीज फंड (जीडीओएफ) में विनोद अडानी के नियंत्रण वाली एक कंपनी ने निवेश किया था। उसके बाद उसने इसको मारीशस में रजिस्टर्ड आईपीई प्लस फंड 1 में निवेश किया।

फाइनेंशियल टाइम्स द्वारा की गयी एक अलग जांच ने बताया था कि जीडीओएफ का पैरेंट फंड दो अडानी एसोसिएट्स द्वारा इस्तेमाल किया गया था। ऐसा उसने अडानी समूह के शेयरों के बड़े हिस्से को हथियाने के लिए किया था।

इस स्थिर फंड को इंडियन इंफोलाइन (आईआईएफएल) द्वारा मैनेज किया जाता है जिसे अब 360 ध्या प्राइवेट फंड डाटा और आईआईएफएल के मार्केटिंग मैटरियल के तौर पर बुलाया जाता है।

आईआईएफएल भारत में सार्वजनिक तौर पर लिस्टेड एक मैनेजमेंट फर्म है जिसका जटिल फंड ढांचे को सेट करने का लंबा इतिहास है। इसके साथ ही जर्मनी के अब तक के सबसे बड़े घोटाले वायरकार्ड स्कैंडल से भी उसका पहले से रिश्ता है। वायरकार्ड से जुड़े एक टेकओवर में आआईएफएल के धन ने कथित तौर पर फ्राड किया था। यूके कोर्ट में दाखिल केस के मुताबिक ऐसा उसने मारीशस फंड स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए किया था।

हम ने पहले इस बात को नोटिस किया कि रेगुलेटरी बॉडी (सेबी) के किसी हस्तक्षेप के जोखिम के बगैर अडानी पूरे विश्वास के साथ आपरेट कर रहे हैं। यह बात इस तरफ इशारा करती है कि ऐसा अडानी का सेबी की चेयरपर्सन माधबी बुच के साथ रिश्तों के चलते हो सकता है। ह्विसिलब्लोअर के दस्तावेजों के मुताबिक ऐसा लगता है कि पहली बार माधबी बुच और उनके पति धवल बुच ने 5 जून, 2015 को सिंगापुर में आईपीई प्लस फंड 1 में अपना एकाउंट खोला। आईआईएफएल में हस्ताक्षरित फंड की घोषणा यह बताती है कि निवेश का स्रोत सैलरी है और दंपति का कुल अनुमानित आय 10 मिलियन डालर है।

उनके लिंकडिन प्रोफाइल के मुताबिक माधबी बुच अप्रैल 2017 में सेबी की होल टाइम मेंबर नियुक्त की जाती हैं।

राजनीतिक तौर पर इस संवेदनशील नियुक्ति के ठीक एक सप्ताह पहले 22 मार्च 2017 को माधबी के पति धवल बुच मारीशस फंड एडमिनिस्ट्रेटर ट्रिडेंट ट्रस्ट को पत्र लिखते हैं। ह्विसिलब्लोअर से मिले दस्तावेज में यह सब कुछ अंकित है। यह ईमेल उनके और उनकी पत्नी के ग्लोबल डायनमिक अपार्च्यूनिटीज फंड (जीडीओएफ) में निवेश से संबंधित था।

पत्र में धवल बुच ने यह निवेदन किया था कि एकाउंट को आपरेट करने वाले वे अकेले आधिकारिक व्यक्ति होंगे। इससे लगता है कि राजनीतिक तौर पर संवेदनशील पद पर नियुक्त होने से पहले अपनी पत्नी की संपत्ति को वहां से वह हटाना चाहते थे।

माधबी बुच के निजी ईमेल को संबोधित 26 फरवरी, 2018 के एक एकाउंट स्टेटमेंट में ढांचे का पूरा विवरण सामने आता है: 'जीडीओएफ सेल 90 (आईपीई प्लस फंड 1)'। एक बार फिर यह मारीशस में रजिस्टर्ड फंड का सेल एक जटिल ढांचे में ढेर सारी पर्तों के साथ गहराई से जुड़ा पाया जाता है जिसे विनोद अडानी द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था।

ह्विसिलब्लोअर का दस्तावेज बताता है कि उसके बाद 25 फरवरी, 2018 को बुच के सेबी के होल टाइम सदस्यता के दौरान वह व्यक्तिगत तौर पर अपने निजी ईमेल एकाउंट का इस्तेमाल कर इंडिया इंफोलाइन को अपने पति के नाम से व्यवसाय करने की बात लिखती हैं, जिससे फंड में इकाइयों को भुनाया जा सके।

संक्षेप में हजारों मुख्यधारा के इज्जतदार आनशोर इंडियन म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट की मौजूदगी के बावजूद एक इंडस्ट्री जिसको रेगुलेट करने की उनको जिम्मेदारी मिली है, दस्तावेज बताते हैं कि सेबी चेयरपर्सन माधबी बुच और उनके पति का एक बहुपर्तों वाले आफशोर फंड ढांचे में स्टेक है। छोटी संपत्ति के साथ, यह बात भी जगजाहिर है कि न्यायिक तौर पर उसके बड़े खतरे हैं, और एक ऐसी कंपनी द्वारा नियंत्रित है जिसका वायरकार्ड घोटाले से रिश्ता है, उसी इकाई में जिसे एक अडानी का निदेशक संचालित करता है, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात उसे विनोद अडानी द्वारा इस्तेमाल किया जाता है जिस पर अडानी के पैसों को साइफन कराने के घोटाले में शामिल होने का आरोप है।

अडानी मामले की सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच कराने के निवेदन के जवाब में कहा जाता है कि आफशोर फंड के धारकों का खुलासा करने के क्रम में सेबी एक दीवार से टकरा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि अडानी के आफशोर शेयरहोल्डर्स को फंड किसने किया सेबी हमारी इन चिंताओं से सहमत थी। लेकिन सही बात यह है कि इस जांच में सेबी बिल्कुल खाली हाथ रही।

अपनी ओरिजनल रिपोर्ट में हमने इस बात को चिन्हित किया था कि दूसरे फंडों में ईएम रिसर्जेंट फंड और इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड दो मारीशस इकाइयां शामिल थीं। इसकी सालाना रिपोर्ट के मुताबिक दोनों इकाइयां इंडिया इंफोलाइन (अब उन्हें 360 ध्या बुलाया जाता है) से संबंधित हैं और उसके कर्मचारियों के जरिये उनकी देखरेख की जाती है।

हमने नोट किया कि इन फंडों का ट्रेडिंग पैटर्न यह बताता है कि स्टॉक पार्किंग इकाइयां और संदिग्ध आफशोर इकाइयां कृत्रिम तौर पर कुछ लिस्टेड अडानी की कंपनियों की कीमतें या फिर उसके वाल्यूम को बढ़ा दी हैं।

हमारी चिंताओं को फाइनेंशियल टाइम्स की एक और जांच ने सही ठहराया जिसमें ईएम रिसर्जेंट और इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड्स के बीच एक गोपनीय पेपर ट्रेल हासिल किया। जांच में यह सवाल उठा कि क्या अडानी समूह भारतीय कंपनियों की शेयर कीमतों को मैनिपुलेट करने पर रोक लगाने के नियमों को बाईपास करने के लिए बिजनेस एसोसिएट्स को फ्रंट मेन की तरह इस्तेमाल करता है।

आज तक सेबी ने इन फंड्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।

27 मार्च, 2013 को अगोरा पार्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड को सिंगापुर में रजिस्टर किया गया था। इसने खुद को बिजनेस और मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के तौर पर घोषित किया था। 2014 की कंपनी की वार्षिक रिटर्न के मुताबिक माधबी बुच इसकी 100 फीसदी स्टेकहोल्डर थीं।

अप्रैल, 2017 में लिंकडिन के मुताबिक माधबी बुच ने होल टाइम मेंबर के तौर पर सेबी ज्वाइन किया और फिर 1 मार्च, 2022 को वह सेबी की चेयरपर्सन बनीं। लेकिन फिर भी वह अगोरा पार्टनर्स की 16 मार्च, 2022 तक 100 फीसदी की हिस्सेदार बनी रहीं। सिंगापुर का रिकार्ड यही बताता है। इस तरह के हितों के टकराहट की राजनीतिक संवेदनशीलता का लगता है ख्याल करते हुए उन्होंने अगोरा पार्टनर्स में अपनी हिस्सेदारी को अपने पति धवल बुच को हस्तांरित कर दिया।

सिंगापुर की यह ऑफशोर इकाई वित्तीय स्टेटमेंट जारी करने की अपनी बाध्यता से अलग है। इसलिए यह साफ नहीं हो पाया है कि यह कितना धन अपने कंसल्टिंग बिजनेस और किससे हासिल किया। यह चेयरपर्सन के बाहरी व्यवसायिक हितों की जांच करने वालों के लिए बेहद महत्वपूर्ण सूचना है।

पहले पेश किए गए सीधे ईमेल के प्रमाण को देखते हुए यह इसलिए विशेष महत्व का हो जाता है कि सेबी चेयरपर्सन माधबी बुच अपने पति के नाम से आफशोर फंड इकाइयों के साथ पाइवेट ईमेल के जरिये बिजनेस कर रही हैं।

सेबी चेयरपर्सन माधबी बुच के पति धवल बुच ने अपने बारे में लिंकडिन पर लिखा है कि सप्लाई चेन के सभी पक्षों और खरीद में गहरा अनुभव। उन्होंने अपना ज्यादातर समय उपभोक्ता कंपनी यूनिलीवर में बिताया जिसमें वह चीफ प्रोक्योरमेंट अफसर तक गए।

यही स्रोत बताता है कि पिछले दो दशकों से वह किसी भी फंड के लिए काम नहीं किए यह रीयल इस्टेट हो या कि कैपिटल मार्केट फर्म।

इन इलाकों में अनुभव की कमी होने के बावजूद उन्होंने एक ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फर्म ब्लैकस्टोन ज्वाइन किया जो भारत में बड़ी निवेश वाली कंपनी है। इसमें उन्हें जुलाई 2019 को पद मिला सीनियर एडवाइजर का।

ब्लैकस्टोन भारत में आरईआईटी को स्पांसर करने वाली और बड़ा निवेश करने वाली फर्मों में से एक है।

भारत का पहला आरईआईटी इंबैसी को सेबी की संस्तुति 1 अप्रैल 2019को मिली जिसको स्पांसर ब्लैकस्टोन ने किया था। यह जुलाई 2019 में बुच के ब्लैकस्टोन ज्वाइन करने से ठीक तीन महीने पहले हुआ।

13 महीने बाद अगस्त 2020 में सेबी की संस्तुति के बाद ब्लैकस्टोन समर्थित माइंडस्पेस आरईआईटी भारत की दूसरी आईपीओ के लिए आरईआईटी बनी।

ब्लैकस्टोन अब नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट को स्पांसर करता है, जिसे आईसीआईसीआई रिसर्च के मुताबिक भारत का सबसे बड़ा असेट का रिटेल प्लेटफार्म कहा जाता है।इसकी लिस्टिंग मई 2023 में हुई और भारत का चौथा ट्रेडेड आरईआईटी बन गया। रिटेल इस्टेट में ब्लैकस्टोन के बहुत दूसरे सारे हित हैं।

ब्लैकस्टोन में धवल बुच के सलाहकार रहने के दौरान सेबी ने ढेर सारे महत्वपूर्ण आरईआईटी रेगुलेशन से संबंधित बदलाव प्रस्तावित किए, पास करवाए और फैसिलिटेट किए।

मार्च 2022 में माधबी बुच के चेयरपर्सन बनने के बाद सेबी ने ढेर सारे आरईआईटी कानून को प्रस्तावित करने के साथ उन्हें लागू किया है, जिन्होंने प्रामाणिक तौर पर ब्लैकस्टोन को फायदा पहुंचाया है। जिसमें उनके पति काम करते हैं।

इसमें दूसरे के अलावा कुछ प्रक्रियागत अपडेट शामिल हैं:

1- आरईआईटीएस पर 7 कंसल्टेशन पेपर

2- आरईआटीएस और एक अमेंडमेंट पर मास्टर सर्कुलर से संबंधित 3 कंसालिडेटेड अपडेट

3- माइक्रो, स्माल और मीडियम आरईआईटीस के लिए एक नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क

4-आरईआटीएस के आफर फार सेल के लिए एक नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क।

5-ब्लैक स्टोन जैसे यूनिट होल्डर को निदेशक नामित करने के लिए नया बोर्ड नामिनेशन

इस दौरान दिसंबर, 2023 में ब्लैकस्टोन ने इंबैसी आरईआईटी में मौजूद अपने पूरे कैश को निकाल लिया। जिसकी कीमत 71 बिलियन रुपये थी यानि 853 मिलियन डालर। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साल का सबसे बड़ा ब्लाक ट्रेड।

### इंदौर विकास प्राधिकरण डकैत और जालसाजों का अड्डा

# अहिल्या पथ स्कीम में अरबो के भ्रष्टाचार में सब चुप क्यों?

इंदौर में माता अहिल्या के नाम इतना बड़ा भ्रष्टाचार खुलेआम हो रहा हैं। इंदौर में जनप्रतिनिधि एंव भाजपा नेता मौन क्यों हैं। इसका जवाब भी जनप्रतिनिधियों को देना चाहिए।

इंदौर विकास प्राधिकरण एंव मोहन सरकार को 500 से 1000 करोड़ की सीधी राजस्व हानि पहुँचाने वाले आईडीए सीईओ राम प्रसाद अहिरवार,पूर्व अध्यक्ष जय पाल सिंह चावड़ा, मंयक जुगवानी,योगेन्द्र पाटीदार,सीसीपी रचना बोचारे एंव टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डायरेक्टर शुभाशीष बनर्जी,डिप्टी डायरेक्टर के.एस.गवली,असिस्टेंट डायरेक्टर सारंग गुप्ता,ज़मीनों के दलाल अतुल काकरिया,सचिन भाईजी सीए सहित टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से ताबड़तोड़ स्वीकृत कराने वाले समस्त 23 भू माफियाओ के खिलाफ म.प्र.सरकार एंव आईडीए को 500 करोड़ से 1000 करोड़ की राजस्व हानि षड्यंत्र रचकर पहुँचाने के अपराध की जॉच हेतु ईडी सहित आर्थिक अपराध ब्यूरो,लोकायुक्त,मुख्यमंत्री,प्रधानमंत्री को सबूतों सहित शिकायत निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर की गई हैं:-

(1) अहिल्या पथ का सीमांकन किया गया खसरा नक्क्षा आईडीए से ज़मीन के दलालों के पास कैसे पहुँचाया गया इसकी जॉच अत्याधिक आवश्यक हैं।

जानकारी के अनुसार आईडीए के मेल आईडी से नक्क्षा दलालों को पहुँचाया गया। सीईओ अहिरवार ने अपने मोबाइल नम्बर से अतुल काकरिया एंव सचिन भाई को मेप पहुँचाया।सभी के डिजीटल डाँटा की जॉच होना चाहिए।स्कीम लगाने के पूर्व ही स्कीम से बाहर करके आईडीए के खर्च पर डेवलपमेंट का बड़ा खेल खुलेआम खेला गया हैं।

(2) अहिल्या पथ स्कीम में शामिल खसरों पर स्कीम पूर्व षड्यंत्र

### कलेक्टर मुख्य कार्यपालन अधिकारी अध्यक्ष इंदौर विकास प्राधिकरण निगम निगम आयुक्त महापौर सबका हिस्सा

रचकर आईडीए और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अधिकारियों ने मिलीभगत करके ताबड़तोड़ नक्क्षे स्वीकृत करने के लिए डिप्टी डायरेक्टर के.एस.गवली ने 35 लाख रूपये प्रति एकड़ का ऊपरी पैसा भू माफियाओ से लिया।इसमें डायरेक्टर शुभाशीष बनर्जी संयुक्त रूप से शामिल हैं।इनके समस्त मोबाइल नम्बर,ई मेल आईडी के साथ समस्त डिजिटल डाँटा की जॉच होना चाहिए।

(3)आईडीए और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अधिकारियों के साथ ज़मीन दलालों के माध्यम से 23 भू माफियाओं ने ताबड़तोड़ 20 अप्रेल 2024 से 20 जून 2024 के मध्य टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से नक्क्षे स्वीकृत कराकर तत्काल डायवर्शन भी करा लिया गया।म.प्र.सरकार एंव आईडीए को सब ने षड्यंत्र रचकर लगभग 1000 करोड़ की राजस्व हानि की हैं।इन सभी के खिलाफ एफ़आइआर दर्ज करके तत्काल समस्त 23 भू माफियाओं के स्वीकृत नक्क्षे निरस्त म.प्र.सरकार करें। जिससे म.प्र. सरकार की 1000 करोड़ की राजस्व हानि बचायी जा सकें।मुख्यमंत्री एंव जॉच एजेंसी तत्काल कार्यवाही करें।

(4) अहिल्या पथ स्कीम भ्रष्टाचार कांड में शामिल समस्त अधिकारियों को तत्काल पदों से मुक्त किया जाये जिससे की भ्रष्टाचार के सबूत नष्ट न कर सकें।आईडीए और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अधिकारियों को तत्काल पदों से जॉच होने तक हटाया जाना चाहिए। डिप्टी डायरेक्टर के.एस.गवली ने अहिल्या पथ पर पूर्व में स्वीकृत नक्क्षों में पत्र देकर 35 लाख रूपये माँगे जा रहें हैं अन्यथा नक्क्षा निरस्त करने के पत्र दिये जा रहें हैं जबकि पिछले चार माह में तथ्य छिपाकर भू माफियाओ के सारे नक्क्षे स्वीकृत करके म.प्र. सरकार को करोड़ों की राजस्व हानि करायी है।

(5) आईडीए सीईओ राम प्रसाद अहिरवार एंव सचिन भाईजी सीए,अतुल काकरिया तथा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के.एस.गवली के मध्य 20 अप्रेल 2024 से 20 जुलाई 2024 के मध्य 235 बार फ़ोन पर आपस के बात हुई।

घोटाला उजागर करने की धोषणा होने के बाद उपरोक्त व्यक्तियों के मध्य 15 अगस्त को दोपहर 12.30 से रात्री 11.30 बजे तक 33 बार बात एंव चारों के मध्य फोन कॉफ्रेंस पर 30 से 35 मिनिट मीटिंग हुई हैं।डिजिटल नक़्शों का आदान प्रदान चारों के मध्य डिजिटल सिग्नल एप के माध्यम से किया गया हैं।इस संदर्भ में जॉच एजेंसी ईडी, लोकायुक्त, आर्थिक अपराध,सीएम,पीएम को नामज़द शिकायत करते हुए समस्त मोबाइल नम्बर,ई मेल,कॉल डिटेल,सिगनल एप चेट,व्हाट्स अप चेट,ई मेल एंव सभी के समस्त लैपटॉप एंव इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की जॉच हेतु समस्त जानकारी सबूतों सहित दी गई हैं।

कांग्रेस महासचिव राकेश सिंह यादव के अनुसार इंदौर में विकास के नाम पर सबसे बड़ा घोटाला सामने आया हैं।

सारे मामले की निष्पक्ष जॉच के लिए उपरोक्त 5 बिंदुओं अनुसार मुख्यमंत्री एंव जॉच एजेंसीयों को तत्काल एफ़आइआर दर्ज करके कार्यवाही शुरू करके म.प्र. सरकार के 1000 करोड़ के राजस्व हानि को बचाना चाहिए।

### कलेक्टर एसडीएम एडीएम से पटवारी तक सब पालते हैं भूमाफिया को

# सैकड़ों पीड़ितों की शिकायतों पर क्यों नहीं होती कार्यवाही

इंदौर में सारे भू कॉलोनी खनन शिक्षा स्वास्थ्य शराब भांग नशा जुआ सट्टा आदि माफियाओं को पालने संरक्षित कर महीना वसूलने वाले भारतीय प्रताड़ना सेवा अधिकारी व भारतीय अपराध संरक्षण सेवा अधिकारियों के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारी अधिकारी ही होकर जनता को लुटवाया करते हैं। ऐसे ही तत्काल में एक मामला संजय दासौद का सामने आया जिसने बंदे ने शहर के आसपास की कृषि भूमि को किसानों से केवल मौखिक बातचीत के दम पर बिना जमीन खरीदे ही कागजों पर विभिन्न नामों से कालोनियां काटकर जनता में और छत की चाहत में अपना मकान खरीदने बनाने के सब्ज बागों के आधार पर प्लॉट काटकर जनता से करोड़ों रुपए हजम कर लिया। शिकायत होने पर कर्मचारियों ने जब तक पैसा नहीं मिला था तब तक वह निवेशकों से शिकायत एवं जानकारी लेते रहे और जब वह पूरी तरीके से उसके सारे जाली दस्तावेज हाथ में आ गए तो उसे सौदेबाजी कर सबको ठंडा बस्ते में डाल दिया।

आप पीड़ितों की कहानी कोई सुनवाई नहीं हो रही। स्वाभाविक सी बात हैइन योजनाओं को कागज पर लाने और जनता को लूटने के पहले उसने सारे नक्शे-बक्श से बनवा करनगर निगम कलेक्ट्रेट गृह एवं ग्राम निवेश विभाग से कागजों पर सील लगवा कर जनता को ठगना शुरू कर दिया।

**इंदौर में भूमाफिया संजय दासौद ने जमीन खरीदे बगैर बेच डाले करोड़ों के प्लाटः** इंदौर में जब से जमीनों के दाम बढ़े हैं, तबसे लूट और धोखेबाजी का खुला खेल जारी है। नए-नए भूमाफिया पनप गए हैं और आम जनता को लूटने के नए-नए तरीके खोज लिए गए हैं। यह सब खुला खेल फर्रुखाबादी की तरह चलता रहा और नगर निगम, प्रशासन,

### क्या सारे अधिकारी कर्मचारियों को संजय दासौद ने टूकड़े डाल मुंह बंद कर दिया

टीएंडसीपी, विकास प्राधिकरण आदि सब आंखें मूंदे बैठे रहे। लोग लुटते गए और माफिया बड़े होते गए।

'साकार रियल लाइफ' जमीन घोटाले में फंसे कॉलोनाइजर संजय दासौद के एक और प्रोजेक्ट पर जांच बैठी है। भूमाफिया दासौद ने किसानों से जमीन खरीदे बगैर प्लाट बेचकर सैकड़ों करोड़ रुपये बटोर लिए। प्री लांचिंग का प्रलोभन देकर बगैर सक्षम अनुमति के खेती की जमीन बेच डाली। फर्जीवाड़ा में दलाल और रियल इस्टेट से जुड़े कारोबारी भी शामिल हैं। सीताबाग निवासी संजय देवेंद्र दासौद ने लवकुश चौराहा से 12 किमी दूरी पर 'शिवनगरी' के नाम से प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी।

दासौद ने दावा किया कि 700 एकड़ जमीन पर कॉलोनी विकसित होगी, जिसमें बड़े-बड़े मंदिर, डी-मार्ट, चौड़ी सड़कें होंगी। सब्जबाग दिखाकर दासौद ने ब्रोकर शुभ संकल्प, फॉर्च्यून, सौरभ के माध्यम से सैकड़ों करोड़ रुपये के प्लाट बेच दिए। जबकि जिन किसानों से जमीन का सौदा हुआ, उन्होंने पूर्ण भुगतान न होने के कारण सौदा निरस्त कर दिया। विकास न होने के कारण प्रोजेक्ट की अनुमतियां ही नहीं आई हैं। एसडीएम प्रदीप सोनी ने मामले में जांच की और पीड़ितों के कथन दर्ज किए, लेकिन अचानक कार्रवाई रोक दी।

### अनुबंध में किया निवेशकों से छलावा

सूत्रों के मुताबिक दासौद निवेशकों से प्लाट के बदले अनुबंध करता है। अनुबंध में ऋण का उल्लेख किया जाता है। उसके बदले जमा राशि का 12 प्रतिशत रिटर्न देने का झांसा देता है। रिटर्न न करने पर अपकमिंग प्रोजेक्ट में प्लाट देने का आश्वासन दिया जाता है। नकद रुपयों के बदले कच्ची रसीदें दी जाती हैं। शिकायत के साथ ऐसी रजिस्ट्री का उल्लेख किया गया है, जो फर्जी व्यक्ति खड़ा कर करवाई गई है।

### हर प्रोजेक्ट में गड़बड़, प्रशासन ने बचाया

भूमाफिया संजय दासौद ने प्रत्येक प्रोजेक्ट में गड़बड़ी की है। साकार कॉरिडोर (बड़ा बांगड़दा), साकार हिल्स (जैतपुरा), सिद्धि विहार (जैतपुरा), साकार कॉरिडोर प्राइम (बड़ा बांगड़दा) साकार रियल लाइफ सिमरोल, शिवनगर (सांवेर रोड) सिंबा सिटी (बायपास) में गड़बड़ी की है। जिला प्रशासन के पास शिकायतें पहुंचीं, लेकिन नोटिस और जांच का बहानाकर फाइलें दबा दी गईं।

### नोटिस जारी किया था

किसी पत्रकार द्वारा शिवनगरी कॉलोनी की शिकायत की गई थी। इसके आधार पर नोटिस जारी किया था। इस मामले में कोई प्लाटधारक भी सामने नहीं आया और न ही ऐसा कोई व्यक्ति सामने आया जो कहे कि हमनें शिवनगरी में प्लाट बुक किया है। इसलिए हमनें शिकायत को खत्म कर दिया। - प्रदीप सोनी, एसडीएम एवं प्रभारी कॉलोनी सेल

### कंपनी सदस्यों की भूमिका की जांच

उधर सिमरोल पुलिस ने बंधक प्लाट बेचने के मामले में आरोपित संजय दासौद, गोपाल गोयल के विरुद्ध जांच शुरू कर दी है। डीआईजी (ग्रामीण) निमिष अग्रवाल के मुताबिक तहसीलदार की रिपोर्ट पर एफआइआर दर्ज की है। पुलिस रजिस्ट्रार, कॉलोनी सेल और टीएनसीपी से दस्तावेज मांग रही है। आरोपितों की कंपनी के अन्य सदस्यों की भूमिका की जांच की जाएगी।

# अनिल अंबानी की तीन कंपनियों के करोड़ों माफ

**अनिल अंबानी की तीन कंपनियों को बैंकों ने 'धोखाधड़ी' के रूप में चिह्नित किया, माल्या, नीरव मोदी के कर्ज से भी ज्यादा यह संचयी रु. 86,188 करोड़ से अधिक है, जो कि विजय माल्या और नीरव मोदी द्वारा भारतीय बैंकों पर बकाया राशि से लगभग दस गुना अधिक है, जिन पर क्रमशः रु. 9,000 करोड़ और रु. 7,409.07 करोड़ का कर्ज है। अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस समूह की तीन संस्थाओं - रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम), रिलायंस इंफ्राटेल और रिलायंस टेलीकॉम (आरटीएल) के बैंक खातों को भारत के तीन प्रमुख उधारदाताओं द्वारा 'धोखाधड़ी' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) और इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) शामिल हैं।**

आरकॉम की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, इस पर रु. 49,193 करोड़ बकाया है। आरकॉम के अलावा रिलायंस टेलीकॉम पर रु. 24,306.27 करोड़ और रिलायंस इंफ्राटेल पर रु. 12,687.65 करोड़ बकाया है। समूह का कुल कर्ज रु. 86,188 करोड़ से अधिक है, जो कि विजय माल्या और नीरव मोदी द्वारा भारतीय बैंकों को दिए गए कर्ज से लगभग दस गुना अधिक है, जिनका कर्ज क्रमशः रु. 9,000 करोड़ और रु.7,409.07 करोड़ है। गिरते हुए अरबपति अनिल अंबानी ने भले ही अपनी नेटवर्थ 'शून्य' होने का दावा किया हो, लेकिन बैंक इस पर यकीन नहीं कर रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स ने बताया कि बैंक इन तीन रिलायंस संस्थाओं के खातों से लेनदेन की जांच शुरू करने पर विचार कर रहे हैं। रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) और रिलायंस टेलीकॉम द्वारा अपने खातों को धोखाधड़ी घोषित करने के खिलाफ याचिका दायर करने के बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय ने यूबीआई और आईओबी को सुनवाई की अगली तारीख यानी 13 जनवरी तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। न्यायालय ने यह भी कहा है कि केंद्र आगे कदम उठा सकता है, मामले की जांच कर सकता है और दोनों कंपनियों के खिलाफ कोई भी शिकायत कार्यवाही दर्ज कर सकता है। बैंक कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए स्वतंत्र हैं। अब तक, एसबीआई और रिलायंस समूह ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। नवीनतम आरोप एक साल बाद आए हैं जब फोरेंसिक ऑडिट में तीन रिलायंस संस्थाओं में 5,500 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेनदेन पाए गए थे। मई 2017 और मार्च 2018 के बीच के लेन-देन की जांच में 100,000 से अधिक प्रविष्टियों की जांच की गई

मोदी 3.0: मोदी कैबिनेट 2024 में पोर्टफोलियो आवंटन के बाद, बाजार को उम्मीद है कि अगले पांच सालों में भारतीय शेयर बाजार में बिजली थीम काम करेगी। पिछले पांच सत्रों से अनिल अंबानी की रिलायंस पावर के शेयर की कीमत आसमान छू रही है, ऐसे में कुछ पर्यवेक्षक अनुमान लगा रहे हैं कि क्या मोदी 3.0 में अनिल अंबानी की रिलायंस पावर के शेयर बाजार के नेता के रूप में उभरेंगे। वे अनिल अंबानी की रिलायंस पावर के शेयरों को लेकर उत्साहित हैं क्योंकि कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो गई है। शेयर बाजार के पर्यवेक्षकों के अनुसार, मोदी 3.0 में बिजली थीम के बारे में चर्चा के बीच, कंपनियाँ कैपेक्स, ट्रांसमिशन नेटवर्क, ईवी और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर, पवन आदि पर काम कर रही हैं। अनिल अंबानी को जल्द ही अपने साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए इन चुनौतियों का सामना करना होगा।

साप्ताहिक समय माया

# भागवत पुराण में वर्णन है

भागवत पुराण में वर्णन है कि जीव को संसार का आकर्षण खींचता है, उसे उस आकर्षण से हटाकर अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो तत्व साकार रूप में प्रकट हुआ, उस तत्व का नाम श्रीकृष्ण है। जिन्होंने अत्यंत गूढ़ और सूक्ष्म तत्व अपनी अठखेलियों, अपने प्रेम और उत्साह से आकर्षित कर लिया, ऐसे तत्वज्ञान के प्रचारक, समता के प्रतीक भगवान श्रीकृष्ण के संदेश, उनकी लीला और उनके अवतार लेने का समय सब कुछ अलौकिक है।

# ...जय कन्हैया लाल की

श्री कृष्णजन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है। योगेश्वर कृष्ण के गीता के उपदेश अनादि काल से जनमानस के लिए जीवन दर्शन प्रस्तुत करते रहे हैं। जन्माष्टमी भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में बसे भारतीय भी इसे पूरी आस्था व उल्लास से मनाते हैं। श्रीकृष्ण ने अपना अवतार भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्यरात्रि को अत्याचारी कंस का विनाश करने के लिए मथुरा में लिया। चूंकि भगवान स्वयं इस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुए थे अतः इस दिन को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। इसीलिए श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा नगरी भक्ति के रंगों से सराबोर हो उठती है।

## मुस्कुराते हुए अवतरण

जन्म-मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन के अवतार का समय था निशीथ काल। चारों ओर अंधेरा पसरा हुआ था। ऐसी विषम परिस्थितियों में कृष्ण का जन्म हुआ कि मां-बाप हथकड़ियों में जकड़े हैं, चारों तरफ कठिनाइयों के बादल मंडरा रहे हैं। इन परेशानियों के बीच मुस्कुराते हुए अवतरित हुए श्रीकृष्ण ने अपने भगवान होने का संकेत जन्म के समय ही दे दिया। कारागार के ताले खुल गए, पहरेदार सो गए और आकाशवाणी हुई कि इस बालक को गोकुल में नंद गोप के घर छोड़ आओ। भीषण बारिश और उफनती यमुना को पार कर शिशु कृष्ण को गोकुल पहुंचाना मामूली काम नहीं था। वसुदेव जैसे ही यमुना में पैर रखा, पानी और ऊपर चढ़ने लगा। श्रीकृष्ण ने अपना पैर नीचे की तरफ बढ़ाकर यमुना को छुआ दिया, जिसके तुरंत बाद जलस्तर कम हो गया। शेषनाग ने उनके ऊपर छाया कर दी ताकि वे भीगे नहीं।

### पूतना का वध

कृष्ण जन्म का समाचार मिलते ही कंस बौखला गया। उसने अपने सेनापतियों को आदेश दिया कि पूरे राज्य में दस दिन के अंदर पैदा हुए सभी बच्चों का वध कर दिया जाए। इधर नंद बाबा के घर कृष्ण जन्म के उपलक्ष्य में लगातार उत्सव मनाया जा रहा था। अभी कृष्ण केवल छह दिन के ही हुए थे कि कंस ने पूतना नाम की राक्षसी को भेजा। पूतना अपने स्तनों में जहर लगाकर बालक कृष्ण को पिलाने के लिए मनोहारी स्त्री का रूप धारण कर आई। अंतर्यामी कृष्ण क्रोध से उसके प्राण सहित दूध पीने लगे और तब तक नहीं छोड़ा, जब तक कि पूतना के प्राणपखेरू उड़ नहीं गए।

स्कन्द पुराण के मतानुसार जो भी व्यक्ति जानकर भी कृष्ण जन्माष्टमी व्रत को नहीं करता, वह मनुष्य जंगल में सर्प और व्याघ्र होता है। ब्रह्मपुराण का कथन है कि कलियुग में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी में अट्ठाइसवें युग में देवकी के पुत्र श्रीकृष्ण उत्पन्न हुए थे। यदि दिन या रात में कलामात्र भी रोहिणी न हो तो विशेषकर चंद्रमा से मिली हुई रात्रि में इस व्रत को करें। भविष्य पुराण का वचन है- श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में कृष्ण जन्माष्टमी व्रत को जो मनुष्य नहीं करता, वह क्रूर राक्षस होता है। केवल अष्टमी तिथि में ही उपवास करना कहा गया है। यदि वही तिथि रोहिणी नक्षत्र से युक्त हो तो 'जयंती' नाम से संबोधित की जाएगी। वह्निपुराण का वचन है कि कृष्णपक्ष की जन्माष्टमी में यदि एक कला भी रोहिणी नक्षत्र हो तो उसको जयंती नाम से ही संबोधित किया जाएगा। अतः उसमें प्रयत्न से उपवास करना चाहिए। विष्णुरहस्यादि वचन से-कृष्णपक्ष की अष्टमी रोहिणी नक्षत्र से युक्त भाद्रपद मास में हो तो वह जयंती नामवाली ही कही जाएगी। वशिष्ठ संहिता का मत है-यदि अष्टमी तथा रोहिणी इन दोनों का योग अहोरात्र में असम्पूर्ण भी हो तो मुहूर्त मात्र में भी अहोरात्र के योग में उपवास करना चाहिए। मदन रत्न में स्कन्द पुराण का वचन है कि जो उत्तम पुरुष है। वे निश्चित रूप से जन्माष्टमी व्रत को इस लोक में करते हैं। उनके पास सदैव स्थिर लक्ष्मी होती है। इस व्रत के करने के प्रभाव से उनके समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। विष्णु धर्म के अनुसार आधी रात के समय रोहिणी में जब कृष्णाष्टमी हो तो उसमें कृष्ण का अर्चन और पूजन करने से तीन जन्मों के पापों का नाश होता है। भृगु ने कहा है- जन्माष्टमी, रोहिणी और शिवरात्रि ये पूर्वविद्धा ही करनी चाहिए तथा तिथि एवं नक्षत्र के अन्त में पारणा करें। इसमें केवल रोहिणी उपवास भी सिद्ध है।

### माखनचोर कन्हैया

माखनचोरी की लीला से कृष्ण ने सामाजिक न्याय की नींव डाली। उनका मानना था कि गायों के दूध पर सबसे पहला अधिकार बछड़ों का है। वह उन्हीं के घर से मक्खन चुराते थे, जो खानपान में कंजूसी दिखाते और बेचने के लिए मक्खन घरों में इकट्ठा करते थे। वैसे माखन चोरी करने की बात कृष्ण ने कभी मानी नहीं। उनका कहना था कि गोपिकाएं स्वयं अपने घर बुलाकर मक्खन खिलाती हैं। एक बार गोपिकाओं की उलाहना से तंग आकर यशोदा उन्हें रस्सी से बांधने लगीं लेकिन वे कितनी भी लंबी रस्सी लातीं, छोटी पड़ जाती। जब यशोदा बहुत परेशान हो गईं तो कन्हैया मां के हाथों से बंध ही गए। इस लीला से उनका नाम दामोदर (दाम यानि रस्सी और उदर यानि पेट) पड़ा।

### ब्रह्मांड के दर्शन

बाल लीला के अंतर्गत कृष्ण ने एक बार मिट्टी खा ली। बलदाऊ ने मां यशोदा से इसकी शिकायत की तो मां ने डांटा और मुंह खोलने के लिए कहा। पहले तो उन्होंने मुंह खोलने से मना कर दिया, जिससे यह पुष्टि हो गई कि वास्तव में कृष्ण ने मिट्टी खाई है। बाद में मां की जिद के आगे अपना मुंह खोल दिया। कृष्ण ने अपने मुंह में यशोदा को संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए। बचपन में गोकुल में रहने के दौरान उन्हें मारने के लिए आततायी कंस ने शकटासुर, बकासुर और तृणावर्त जैसे कई राक्षस भेजे, जिनका संहार कृष्ण ने खेल-खेल में कर दिया।

## जन्माष्टमी 26 या 27 अगस्त 2024 कब? सही तारीख, कान्हा की पूजा का शुभ मुहूर्त जानें

कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मथुरा नगरी में असुर कंस के कारागृह में देवकी की आठवीं संतान के रूप में भगवान श्रीकृष्ण ने जन्म लिया था. श्रीकृष्ण को विष्णु जी का अवतार माना जाता है.

मान्यता है कि हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी यानि जन्माष्टमी पर श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करने पर हर दुख, दोष, दरिद्रता दूर होती है. इस साल कृष्ण जन्माष्टमी 2024 की डेट को लेकर कंफ्यूजन है तो यहां जानें जन्माष्टमी की सही तारीख, पूजा मुहूर्त और महत्व.

कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त 2024 को मनाई जाएगी. इस दिन घरों में झाकियां सजाई जाती है, भजन-कीर्तन किए जाते हैं. कृष्ण भक्त व्रत कर, बाल गोपाल का भव्य श्रृंगार करते है, रात्रि में 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में कान्हा का जन्म कराया जाता है.

श्रीकृष्ण की जन्मभूमि मथुरा और वृंदावन में जन्माष्टमी 26 अगस्त 2024 को मनाई जाएगी. यहां जन्माष्टमी की रौनक बहुत खास होती है. बांके बिहारी के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लगी होती है.

Vastu Tips

# वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में रखें बहते झरने के शो पीस

आपने कई लोगों के घरों में देखा होगा कि बहते हुए झरने, नदियों और पानी की तस्वीर या शो पीस रहते हैं। ऐसे में वास्तु की दृष्टि से बहुत कम लोग इसका महत्व जानते हैं, वास्तुशास्त्र के अनुसार माना जाता है बहते हुए पानी की तस्वीर घर में लगाना शुभ होता है। इन तस्वीरों या शो पीस को घर में लगाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए।

घर के सदस्यों या फैमिली बिजनेस को बेडलक या लोगों की बुरी नजर से बचाए रखने के लिए गलियारे या बालकनी में पानी से संबंधित कोई तस्वीर या शो पीस रखना चाहिए।

पानी से जुड़ा कोई भी शो पीस या तस्वीर किचन में नहीं लगाना चाहिए।

यदि आप फाउंटेन घर में लगवा रहे हैं तो इसे घर की उत्तर या दक्षिण-पूर्व दिशा में लगवा सकते हैं।

घर की उत्तर-पूर्व दिशा में मिट्टी के बने बर्तन या सुराही में पानी भरकर रखना चाहिए। ऐसा करने से घर के लोगों का दुर्भाग्य खत्म होता है और हर काम में सफलता मिलती है। ●

# घर के दरवाजे होने चाहिए सही दिशा में

घर के दरवाजे बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। प्रत्येक दिशा का दरवाजा लाभ के साथ नुकसान भी देता है। हालांकि परंपरागत अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि उत्तर, ईशान और पूर्व मुखी मकान ही शुभ फलदायी होते हैं।

**पूर्व:** पूर्व दिशा में घर का दरवाजा है कई मामलों में शुभ है लेकिन ऐसा व्यक्ति कर्ज में डूब जाता है।

**पश्चिम:** पश्चिम दिशा में दरवाजा होने से घर की बरकत खत्म होती है।

**उत्तर:** उत्तर दिशा का दरवाजा शुभ फल ही देता है।

**दक्षिण:** दक्षिण दिशा का दरवाजा है तो लगातार आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

**आग्नेय:** आग्नेय दिशा का दरवाजा घर में रोग उत्पन्न करता है।

**ईशान:** ईशान दिशा के दरवाजे के सामने किसी भी प्रकार का वास्तुदोष नहीं है तो यह शुभफलदायी होता है।

**नैऋत्य:** यह दिशा भी दक्षिण और आग्नेय दिशा की तरह फल देने वाली होती है।

**वायव्य:** वायव्य दिशा के दरवाजे का फल भी पश्चिम और उत्तर की तरह हो सकता है, लेकिन यह दिशा सही नहीं है तो पड़ोसी से संबंध खराब हो सकते हैं। ●

# माथे की लकीरें बताती हैं भविष्य

माथे की लकीरों का कनेक्शन भाग्य से जुड़ा है। सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक किसी भी व्यक्ति के माथे की लकीरों को देखकर यह ज्ञात किया जा सकता है कि वह कितना भाग्यशाली है। माथे की ये लकीरें व्यक्ति के भूत, वर्तमान और भविष्य की ओर इशारा करती हैं।

**धन से जुड़ी माथे की पहली लकीर**

सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक व्यक्ति के माथे की पहली लकीर का संबंध धन से होता है। यह लकीर भौं के निकट बनती है। इसे धन की लकीर भी कहते हैं।

जिस व्यक्ति की धन की यानी माथे की पहली लकीर जितनी स्पष्ट होगी, वह व्यक्ति उतना ही धनवान होगा।

**माथे की दूसरी लकीर सेहत की देती है जानकारी**

व्यक्ति के स्वास्थ्य जीवन से जुड़ी है माथे पर बनी दूसरी लकीर। यह लकीर भौंहों के निकट की लकीर के बाद दूसरी लकीर होती है। अगर माथे की दूसरी लकीर गाढ़ी और साफ दिखाई देती है तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति का स्वास्थ्य जीवन अच्छा होगा। इसके विपरीत यह लकीर पतली और हल्की होती है तो व्यक्ति को स्वास्थ्य परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

**भाग्य से है माथे की तीसरी लकीर का कनेक्शन**

माथे पर पड़ने वाली नीचे से तीसरी लकीर भाग्य की लकीर होती है। खास बात ये है कि यह लकीर बहुत ही कम लोगों के माथे पर होती है। जाहिर सी बात है कम लोग ही भाग्यशाली होते हैं। अगर यह लकीर माथे पर बनी होती है तो वह व्यक्ति भाग्यशाली होता है।

**जीवन के उतार-चढ़ाव से जुड़ी है चौथी**

माथे पर बनने वाली चौथी लकीर का संबंध जीवन में आने वाले उतार-चढ़ाव से होता है। हालांकि ये लकीर 26 से 40 वर्ष तक के उतार-चढ़ाव और संघर्ष के बारे में बताती है। ऐसे व्यक्ति चालीस की उम्र के बाद सफलता की बुलंदियों में होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का आर्थिक जीवन भी अच्छा होता है।

**पांचवीं लकीर का है ये मतलब**

माथे पर बनने वाली पांचवीं लकीर को खतरनाक माना जाता है। यह लकीर जीवन में तनाव और चिंता को दर्शाती है।

**छठी लकीर वाले करते हैं अप्रत्याशित उन्नति**

माथे पर छठी लकीर नाक की सीधी तरफ ऊपर जाने वाली लकीर को कहते हैं। इसे दैवीय लकीर कहा जाता है। क्योंकि यह लकीर संकेत देती है कि व्यक्ति के ऊपर दैवीय कृपा है। ●

# प्रेम और वैवाहिक जीवन में प्यार का रस घोलती हैं ये फेंगशुई टिप्स

फेंगशुई चीनी ज्योतिष में वास्तु दोष को खत्म करने का बेहतरीन उपाय है। फेंगशुई टिप्स जीवन की सकारात्मक शक्तियों को नष्ट करती हैं और सकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। हमारे वातावरण में चारों ओर कई तरह की नकारात्मक ऊर्जा विद्यमान होती हैं और ये निगेटिव पावर हमारे जीवन को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करती हैं। परंतु घर या कार्यस्थल पर फेंगशुई उपाय के कारण नकारात्मक ऊर्जा प्रभाव शून्य हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। यहां कुछ ऐसे फेंगशुई टिप्स की बात कर रहे हैं, जिसे अपनाकर आप अपने प्रेम जीवन को मधुर और प्रगाढ़ बना सकते हैं। यह फेंगशुई टिप्स खासतौर पर बेडरूम के लिए है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में किसी तरह की दिक्कतें आ रही हैं तो ये दिक्कतें भी इस उपाय से आसानी से दूर होंगी।

फेंगशुई के अनुसार अगर आप शादीशुदा हैं, तो अपने बेडरूम में टी.वी., कंप्यूटर आदि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को न रखें।

फेंगशुई में बेड के सामने टॉयलेट का गेट न होने की सलाह दी गई है। अगर ऐसा हो भी तो हमेशा बंद रखें।

बेड के सामने कभी-भी मिरर नहीं होना चाहिए। फेंगशुई के मुताबिक इससे पति-पत्नी में तकरार होने की संभावना बनी रहती है।

डबल बेड पर सिंगल गद्दे इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा करने से रिश्ते में आई नकारात्मकता दूर होती है और दोनों का रिश्ता मजबूत होता है।

बेड को हमेशा सिरा खिड़की या दीवार से हटा कर रखें। दीवार से सटा कर रखने से संबंधों में तनाव पैदा होता है।

बेड के नीचे किसी भी तरह का सामान नहीं रखें। इससे बेडरूम में सकारात्मक ऊर्जा का फ्लो अच्छा रहेगा। ●

# परेशानियों से बचने के लिए घर में रखें फेंगशुई ऊंट

अगर आप बुरे वक्त के दौर से गुजर रहे हैं, तो घर में फेंगशुई गैजेट ऊंट की स्थापना करें। यह आपको परेशानियों से निजात दिलाएगा।

> *अगर आपके परिवार में आए दिन कोई न कोई बीमार रहता है या परिवार के किसी सदस्य को बीमारी, दुर्घटना आदि का खतरा बना रहता है, तो यह गैजेट निश्चित रूप से उसके लिए सहायक साबित हो सकता है।*

समझदार वही है, जो बुरे दिनों के लिए पहले से तैयार रहता है। बात चाहे रुपए-पैसे की हो या स्वास्थ्य की, आर्थिक तंगी से निपटने के लिए हम नियमित बचत करते हैं तो बीमारी, रोग आदि के लिए मेडिकल इंश्योरेंस करवाते हैं।

यह बताने की जरूरत नहीं कि ये सब चीजें बुरे समय में हमारे कितनी काम आती हैं। आज फेंगशुई के जिस गैजेट के बारे में बता रहे हैं, वह न सिर्फ बुरे समय में हमारे लिए सहायता का काम करता है, बल्कि उसकी स्थापना हमें आने वाली विपदा व दुर्भाग्य से भी बचाती है। यह गैजेट है फेंगशुई ऊंट। जिस तरह यह जानवर विलक्षण क्षमताओं वाला है, उसी प्रकार फेंगशुई गैजेट के रूप में भी इसके प्रभाव विलक्षण हैं। ऊंट एकमात्र ऐसा जानवर है, जो विपरीत परिस्थितियों में कई दिनों तक बिना खाए-पीए रहकर भी अपने सवार को उसकी मंजिल तक पहुंचाने का लक्ष्य रखता है।

अगर आपके परिवार में आए दिन कोई न कोई बीमार रहता है या परिवार के किसी सदस्य को बीमारी, दुर्घटना आदि का खतरा बना रहता है, तो यह गैजेट निश्चित रूप से उसके लिए सहायक साबित हो सकता है।

हमारी आधी से अधिक चिंताओं और परेशानियों की वजह होती है आर्थिक समस्या। आपको अपने निवेश का उचित प्रतिफल मिले और आपके पास कैश फ्लो यानी नगद की आवक बनी रहे तो इसके लिए फेंगशुई ऊंट को घर के उत्तर-पश्चिम में स्थापित करना चाहिए।

साप्ताहिक समय माया

# भाजपा को अपनी 60,000 करोड़ रुपये की अघोषित कमाई का रहस्य बताना होगा

**पिछले कुछ वर्षों में जहां भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार संकटग्रस्त होती जा रही है, वहीं भाजपा लगातार अमीर होती जा रही है। जो पैसा उसने अपने सैकड़ों भव्य कार्यालयों के निर्माण पर, और अपने चुनाव प्रचार अभियान पर खर्च किया है, पार्टी द्वारा घोषित आय की तुलना में वह कई गुना ज्यादा है।**

उत्तर-पश्चिमी तमिलनाडु में बेंगलोर-चेन्नई राष्ट्रीय राजमार्ग पर, कृष्णागिरि शहर से तीन किलोमीटर दूर, एक चमकदार नई इमारत खड़ी है। यह तमिलनाडु के कृष्णागिरि जिले में भाजपा का नया पार्टी कार्यालय है।

पिछले साल ही इस पांच मंजिला इमारत का उद्घाटन किया गया था। यह लगभग 12 मीटर चौड़ी और 16 मीटर लंबी; नारंगी हाइलाइट्स के साथ क्रीम और सफेद रंग में रंगी हुई है, जैसे कोई आवासीय अपार्टमेंट हो। लेकिन दो चीजें अजीब हैं।

एक, तो सामने काफी बड़ी पार्किंग है जिसका क्षेत्रफल भवन के क्षेत्रफल से तीन गुना ज्यादा है। दूसरे, इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का ट्रेडमार्क भगवा और हरा कमल उकेरा गया है।

अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी, कि सभी राज्यों और जिलों में 'सभी आधुनिक संचार सुविधाओं से सुसज्जित' पार्टी के कार्यालय होने चाहिए। अगले ही साल बीजेपी ने देश के 694 में से 635 जिलों में नये कार्यालय बनाने का फैसला किया। मार्च 2023 तक, उस लक्ष्य को बढ़ाकर 887 जिला पार्टी कार्यालयों तक कर दिया गया था।

इसके पीछे एक ठोस तर्क था। जैसा कि भाजपा के महासचिव अरुण सिंह ने 2020 में इकोनॉमिक टाइम्स को बताया था, 'पहले कोई विधायक या स्थानीय नेता अपने घर में कार्यालय बनाता था। इस वजह से कई अन्य नेता कार्यालय नहीं आते थे। चूंकि पार्टी बड़ी हो गयी है, इसलिए उसके पास लाइब्रेरी, कॉन्फ्रेंस हॉल और वीडियो और ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम जैसी सभी सुविधाओं से सुसज्जित अपने कार्यालय होने चाहिए।'

मार्च 2023 में, कृष्णागिरि कार्यालय पहुंच कर उसका उद्घाटन करते हुए, तथा उसी के साथ तमिलनाडु के नौ अन्य कार्यालयों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करते हुए, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संवाददाताओं से कहा कि 290 जिला कार्यालयों पर काम पूरा हो चुका है। बाकी पर काम चल रहा है। भाजपा की इन निर्माण परियोजनाओं पर अभी तक उतना ध्यान नहीं दिया गया है, जितना चाहिए था।

भाजपा का निर्माण अभियान

आकार के लिहाज से, कृष्णागिरि में पार्टी कार्यालय कोई अजूबा नहीं है। जैसा कि 'टाइम्स ऑफ इंडिया' ने 2016 में बताया था, ओडिशा में भी, भाजपा के नये जिला कार्यालयों का निर्माण क्षेत्र लगभग 10,000 वर्ग फुट, प्रचुर पार्किंग स्थान और 250-300 लोगों के बैठने की क्षमता वाला एक सम्मेलन कक्ष है। अन्य जिला कार्यालय भी काफी बड़े हैं, चाहे मणिपुर में हों (जैसे कि थौबल में पार्टी कार्यालय, जिसे हाल ही में जला दिया गया), केरल (कन्नूर) या हिमाचल प्रदेश (ऊना) में।

ये 290 से अधिक जिला कार्यालय केवल शुरुआत हैं। भाजपा बड़े शहरों में भी पार्टी कार्यालय बना रही है। इनमें से कई काफी बड़े हैं, अच्छी तरह से सुसज्जित हैं और बेहद खास जगहों पर बनाये गये हैं।

उदाहरण के लिए, 2018 में, पार्टी ने मध्य दिल्ली के दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर अपने नये 1,70,000 वर्ग फुट के मुख्यालय का अनावरण किया, जो शहर के कनॉट प्लेस शॉपिंग परिसर से एक किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। इसके पहले भाजपा के मुख्य कार्यालय, अशोक रोड के लुटियंस बंगलो, 11 नंबर, और उससे सटे हुए, 9 नंबर के क्षेत्रफल की तुलना शायद ही इस नये भव्य कार्यालय परिसर से की जा सके। इसके उद्घाटन के मौके पर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि नया कार्यालय दुनिया के किसी भी अन्य राजनीतिक दल के कार्यालय से बड़ा है। जबकि भाजपा अभी भी 11, अशोक रोड का उपयोग अपने आईटी सेल के मुख्यालय और अपने चुनाव 'वॉर रूम' के रूप में कर रही है।

एक और उदाहरण लेते हैं। 2021 में, भाजपा ने दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेसवे पर सिग्नेचर टॉवर क्रॉसिंग पर गुड़गांव भाजपा के लिए एक नये कार्यालय का अनावरण किया। कार्यालय के बारे में बताते हुए, 'हिंदुस्तान टाइम्स' ने बताया कि यह 'लगभग 100,000 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला हुआ हैष्ठ इसमें पुस्तकालय, मीडिया कक्ष, आईटी कक्ष और विभिन्न पार्टी प्रकोष्ठों के लिए अलग-अलग अहाते हैं।' इसमें बेसमेंट पार्किंग की भी दो मंजिलें हैं; एक सभागार है जहां 600-700 लोग बैठ सकते हैं; दो बड़े सम्मेलन कक्ष; और अन्य जिलों और राज्यों से आने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए आवासीय व्यवस्था है। इसकी लागत अज्ञात है।

दो साल बाद, मोदी ने भाजपा के इस नये मुख्यालय वाली सड़क के पार बने एक आवासीय-सह-सभागार परिसर का उद्घाटन किया। मीडिया ने बताया कि इसका उपयोग पार्टी के महासचिव/मंत्री स्तर के नेताओं और बड़ी पार्टी बैठकों के लिए किया जाएगा।

भारत के कई अन्य शहरों में भी नये कार्यालय खुले हैं, जैसे कि त्रिवेन्द्रम और ठाणे में। पार्टी दिल्ली भाजपा और मध्य प्रदेश भाजपा के लिए भी नये कार्यालय बना रही है।

'इकोनॉमिक टाइम्स' की 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार, भाजपा के दिल्ली कार्यालय में दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला से भी डिजाइन ली गयी है। यह मध्य दिल्ली में 825 वर्ग मीटर के भूखंड पर बन रहा है; और इसका निर्मित क्षेत्र 30,000 वर्ग फुट है। दिल्ली बीजेपी के कोषाध्यक्ष विष्णु मित्तल ने अखबार को बताया, ''इमारत में 50 वाहनों की पार्किंग के लिए दो बेसमेंट होंगे।''

जैसा कि मित्तल ने अखबार को बताया, इसके भूतल पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कक्ष, रिसेप्शन और कैंटीन होगी। प्रथम तल पर 300 लोगों की बैठने की क्षमता वाला एक सभागार है। दूसरी मंजिल पर दिल्ली भाजपा के प्रकोष्ठों और कर्मचारियों के कार्यालय हैं। तीसरी मंजिल पर पार्टी उपाध्यक्षों, महासचिवों और सचिवों के कार्यालय हैं। और, शीर्ष मंजिल पर, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष और महासचिव (संगठन) के कार्यालयों के अलावा दिल्ली के सांसदों और राज्य इकाई के प्रभारियों के लिए कमरे हैं।

हलांकि इन सभी इमारतों की लागत अज्ञात है, फिर भी, भोपाल में मध्य प्रदेश भाजपा के नये कार्यालय की लागत लगभग 100 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इसी तरह, असम भाजपा का पार्टी कार्यालय एक लाख वर्ग फुट में बनाया गया है, जिसमें एक गेस्ट हाउस, एक आधुनिक मीडिया सेंटर, पांच मीटिंग हॉल और 350 सीटों वाला सभागार है, जिसमें 5,000 लोग रह सकते हैं और इसकी कीमत 25 करोड़ रुपये है।

कुल मिलाकर, इन निर्माण कार्यों का पूरा विवरण अज्ञात है। अतीत में, नड्डा ने 900 नये पार्टी कार्यालयों का अनुमान बताया था। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि इनमें से कितने कस्बों और शहरों में बन रहे हैं। इस ताबड़तोड़ निर्माण अभियान के पीछे एक जटिल प्रश्न छिपा हुआ है।

**एक विचित्र विरोधाभास की कहानी**

जब तक यह लेख प्रेस में जाएगा, 2024 के चुनावों के पहले दो चरण खत्म हो चुके होंगे। इस बार चुनाव पहले की तुलना में अधिक फीका लग रहा है। इसके संभावित कारणों पर काफी लिखा गया है। जैसे कि, एक मजबूत विपक्ष की अनुपस्थिति; एक ऐसा चुनाव जिसमें आधिकारिक तौर पर मुद्दे ही नहीं हैं; या कई चरणों और महीनों तक विस्तृत मतदान अवधि। इन सबके अलावा मतदाता की थकान भी एक कारण है। जब तक वे नोटबंदी और जीएसटी के आर्थिक झटकों से उबर पाते, भारतीयों पर कोविड का हमला हो गया, जिसमें राज्य ने उनके साथ बेहद खराब व्यवहार किया। नतीजा यह हुआ कि अर्थव्यवस्था काफी ग़ैर-बराबरी के साथ पटरी पर लौटी, जिसमें बेहद अमीरों को बेहिसाब मुनाफा हुआ, जबकि शेष पूरा देश बेरोजगारी के भंवर में फंस गया। आज का समय ऐसा है जब भारत में आय असमानता 100 साल के उच्चतम स्तर पर है; और लोग पहले की तरह बचत नहीं कर पा रहे हैं।

लेकिन आम देशवासियों के इस संघर्ष के विपरीत, भाजपा की अर्थव्यवस्था में नाटकीय सुधार देखा गया है। यह न केवल चुनावों में प्रतिद्वंद्वियों पर भारी पड़ रही है, बल्कि मार्च 2023 तक भाजपा ने 5,400 करोड़ रुपये की भारी-भरकम नकदी का भंडार बनाये रखते हुए भी इसने बेहिसाब अचल संपत्ति भी जमा कर लिया है।

इमारतों में पार्टी का निवेश तो साफ-साफ दिख रहा है। लेकिन इसने राज्य और राष्ट्रीय चुनावों में किये गये खर्च के मामले में भी अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। 2019 के चुनावों और वर्तमान चुनावों, दोनों में यही स्थिति है। भाजपा पर, अपनी सत्ता बनाये रखने के लिए, बार-बार प्रतिद्वंद्वी दलों में दलबदल कराने का भी आरोप लगाया गया है और विपक्षी नेताओं और प्रमुख नागरिकों पर निगरानी रखने के लिए सरकार द्वारा 'पेगासस' जैसे महंगे हाई-टेक स्पाइवेयर और और उसके नये वेरिएंट्स के इस्तेमाल के भी आरोप लगाये गये हैं।

**तो आखरी भाजपा के पास कितना पैसा है?**

हलांकि यह सबको पता है कि भारत के राजनीतिक दल चुनाव आयोग को अपनी वित्तीय रिपोर्ट बेहद पवित्र बनाकर पेश करते हैं, इसके बावजूद इस सवाल पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, जितना दिया जाना चाहिए। पार्टियां अपनी पूरी आय नहीं बतातीं। सत्ता सुनिश्चित करने के लिए वे जो खर्च करती हैं और जिन संसाधनों का इस्तेमाल करती हैं, वे उसका खुलासा नहीं करतीं, या उसके बेहद छोटे हिस्से को ही दिखाती हैं।

भाजपा के मामले में, यह एक विशेष रूप से हैरतअंगेज चूक है। पार्टी की वित्तीय स्थिति का करीबी जायजा लिया ही नहीं गया है। हलांकि, रायपुर स्थित एक राजनीतिक पर्यवेक्षक ने 'द वायर' को बताया, 'भाजपा का चुनावी प्रभुत्व उसके वित्तीय प्रभुत्व से पैदा होता है।'

इसके बावजूद, देश के राजनीतिक टिप्पणीकारों ने, भाजपा की जीत जारी रखने की क्षमता पर अपने विशेष स्तम्भों और किताबों में, पार्टी के अर्थशास्त्र की जांच नहीं की है। इस सोचे-समझे अंधेपन की कीमत बहुत अधिक है। भाजपा के सत्ता में आने के दस साल बाद भी, भारतीयों को पता नहीं है कि इस पार्टी की जेब कितनी गहरी है, न यही पता है कि इतना भारी-भरकम वित्तीय रिजर्व कैसे बनाया गया है।

हलांकि, पार्टी द्वारा व्यय की दो प्रमुख मदों, इसके भवन-निर्माण कार्य, और इसके चुनाव अभियान के खर्चों पर एक नज़र डालने से कुछ सांकेतिक संख्याएं उभर कर सामने आती हैं, जो यह बताती हैं कि 2014 और 2023 के बीच भाजपा द्वारा आधिकारिक तौर पर घोषित आय 14,663 करोड़ रुपये, इसकी वास्तविक आय से बहुत कम है।

1. बीजेपी अपनी नई इमारतों पर कितना खर्च कर रही है?

पार्टी के खर्च पर नज़र रख कर ही इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। आइए इमारतों पर हुए खर्च से शुरुआत करते हैं। 2014-15 और 2022-23 के बीच अपनी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, भाजपा ने भूमि और भवनों पर 1,124 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

2016 में बताया गया था कि ओडिशा में बनने वाले प्रत्येक जिला कार्यालय की लागत 2 करोड़ रुपये से 3 करोड़ रुपये के बीच होगी। यानि 36 कार्यालयों के लिए कुल 80 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

वह लगभग आठ साल पहले की बात है। जमीन की क़ीमतों और निर्माण लागत में उछाल को देखते हुए, हाल में बनायी गयी इमारतों की लागत अधिक होने की संभावना है। उदाहरण के लिए, कृष्णागिरि कार्यालय, चेन्नई-बैंगलोर राजमार्ग पर स्थित है, जो बहुत तेज औद्योगिकीकरण वाले इलाक़े, होसुर, से बमुश्किल तीस मिनट की दूरी पर है।

एक स्थानीय बिल्डर ने 'द वायर' को बताया कि यहां जमीन की दरें 5,000 रुपये प्रति वर्ग फुट हैं । यानि, प्लॉट के लिए लगभग 5 करोड़ रुपये का खर्च।

उन्होंने कहा कि बुनियादी निर्माण पर 1,500 रुपये प्रति वर्ग फुट की लागत आएगी जो 3,000 रुपये प्रति वर्ग फुट तक भी जा सकता है। कुल मिलाकर, उन्होंने निर्माण की संभावित लागत कम से कम 1.5 करोड़ रुपये आंकी। उन्होंने कहा, ''एक अच्छी तरह से सुसज्जित इमारत की लागत करीब 3 करोड़ रुपये होगी।''

मार्च 2023 में, नड्डा ने कहा कि 290 पार्टी कार्यालय पूरे हो चुके हैं। अगर हम यह मान लें, कि इन इमारतों (भूमि और भवन को मिलाकर) की लागत पिछले आठ वर्षों में 3 करोड़ रुपये पर स्थिर बनी हुई है, तब भी पार्टी का परिव्यय अकेले जिला कार्यालयों पर 870 करोड़ रुपये बैठता है। सभी 887 जिला कार्यालयों के लिए, पार्टी का नियोजित परिव्यय 2,661 करोड़ रुपये हो जाता है।

पार्टी बड़े शहरों में बड़े कार्यालय भी बना रही है। जैसा कि इस लेख में ऊपर कहा गया है, इसके गुवाहाटी कार्यालय की लागत 25 करोड़ रुपये है और भोपाल कार्यालय की लागत 100 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है। प्रति राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक बड़े कार्यालय, 25 करोड़ रुपये की दर से, कुल 900 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च जोड़ लिया जाए, तो सभी पार्टी कार्यालयों पर कुल खर्च 3,500 करोड़ रुपये पहुंच जाता है।

यह संख्या ज्यादा भी हो सकती है। जिला कार्यालयों पर 3 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आ सकती है। उदाहरण के लिए, ओडिशा में जमीन का बाजार मूल्य बिक्री-पत्र में उल्लिखित मूल्य से अधिक बताया गया है। पार्टी प्रत्येक राज्य में एक से अधिक बड़े कार्यालय बना सकती है। इसके अलावा, जैसे हालात हैं, कांग्रेस नेता कमल नाथ ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने अकेले अपने दिल्ली मुख्यालय पर 700 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

'द वायर' ने पार्टी की निर्माण योजनाओं और बजट के विवरण के लिए भाजपा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल को ईमेल किया है। पार्टी के संयुक्त कोषाध्यक्ष नरेश बंसल को भी प्रश्न ईमेल किए गये हैं। इसके बाद दोनों को व्हाट्सएप पर भी इन ईमेल के बारे में जानकारी दी गयी। उनसे जवाब मिलने पर यह लेख अपडेट कर दिया जाएगा।

2. बीजेपी चुनाव प्रचार पर कितना खर्च कर रही है?

वित्त वर्ष 2015-16 और वित्त वर्ष 2022-23 के बीच के वर्षों के लिए, भाजपा की वार्षिक रिपोर्ट में चुनाव प्रचार ('चुनाव/सामान्य प्रचार') पर कुल 5,744 करोड़ रुपये खर्च बताया गया है। हलांकि, 'सेंटर फ़ॉर मीडिया स्टडीज़' (सीएमएस) जैसे स्वतंत्र अध्ययन, अकेले 2019 के चुनावों में पार्टी का खर्च '27,000 करोड़ रुपये के करीब' आंकते हैं। वास्तविक रिपोर्टें भी पार्टी उम्मीदवारों के चुनाव खर्च को चुनाव आयोग की प्रति

# जनता से हर कदम लूट, दुर्घटनाओं से मौत का तांडव

**पेज 1 का शेष**

दूसरी तरफ इन जालसाज हरामखोरों ने जनता को लूटने के लिए जो हर छोटी व लंबी दूरी की ट्रेनों में 3-4 बोगी अनारक्षित व द्वितीय श्रेणी के आधे से ज्यादा बोगी हुआ करते थे जनता कुल्लू में अनारक्षित को पूर्ण तरीके से समाप्त कर दिया और द्वितीय श्रेणी आरक्षित को भी मात्र 3 से 5 बोगी ही लगाने के साथ अधिकांश ए सी डब्बे लगाई जाने लगे जिनके रास्ते में ऐ सी खराब हो जाते हैं अधिकांश के एसी बिगड़े रहते हैं। रास्ते में खराब हो जाते हैं। बंद हो जाने के साथ-साथ उसमें जो कंबल चादर हुआ बिस्तर मिलता था। वे कंबल चादर भी अब नहीं मिलते और मिलते भी हैं तो अत्यधिक बदबूदार महीनों से गंदे अनधुले जो बीमारियां पैदा करते हैं। लाख शिकायत होने के बाद में भी कहीं कुछ नहीं होता। रेलवे में यात्रियों की सुरक्षा के लिए चलने वाली रेलवे पुलिस का फोर्स भी काम कर दिया गया। कार्यरत पुलिस कर्मियों के कार्य घंटे भी 68 से बढ़कर 12-16 कर दिए गए। उससे रेलवे में चोरी लूट बलात्कार भी बढ़े। जिन की खबरें दवा दी जाती है। जहां एक तरफ रेलवे में पुलिस फोर्स की भर्ती नहीं की जा रही। वही लोको इंजीनियर से लेकर वर्कशॉप लाइन इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल्स इंजीनियरों से लेकर अन्य सभी तकनीकी लगभग 5 लाख कर्मचारी और इसी प्रकार 5 लाख से ज्यादा सफाई कर्मियों से लेकर बाबुओं अधिकारियों आदि की भी भर्ती को पूरी तरह से बंद कर रखा है और सफाई से लेकर अधिकांश कार्य ठेके पर चलाए जा रहा है यहां तक की माल गोदाम की बुकिंग में भी ठेका प्रथा शुरू हो गई है प्लेटफार्म पर रेलवे की बोगियां आदि भी सब ठेकेदारी पर चलाई जा रही है और उसमें मोटी कमाई करने के साथ-साथ लगभग 10 लाख से ज्यादा कर्मचारियों का दिन से 10 से लेकर 16 घंटे तक काम लेने के बाद में भी उन्हें 8000-10000 ही वेतन दे रहा है उनका ठेकेदार। अधिकांश बोगियों से लेकर रेलवे के डीजल व इलेक्ट्रिकल इंजनों की भी हालात भारी खराब है। जिनका समय बना तो मेंटेनेंस किया जाता है नहीं उसमें आवश्यकता का तेल पानी भारत डाला जाता है सारा खेलकाम चलाओ होने के कारण चारों तरफ दुर्घटनाओं की बाढ़ आई हुई है। इस पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव व्यवस्था सुधारने की बात तो दूर उल्टे ही वह जालसाज हरामखोर डकैत संसद में शिकायत करने और प्रश्न पूछने वाले सांसदों को उल्टा ही जवाब देता है और न केवल संसद में उल्टा जवाब दिया जाता है बल्कि मीडिया को भी डराने धमकाने और मोटा पैसा बांटने के साथ अपने हिसाब से चलने का खेल सन 2014 से ही चलने लगा था। इस खबर को बुलाने के लिए मैंने गूगल याहू एमएसएन पर कई बार खोजा। तो वहां पर भी बड़ी बदतमीजी की पूर्ण तरीके से जो परिणाम दिखाए गए उसमें उल्टा ही अपनी नाकामियों को छुपाने लिखा गया की सन 2004 से 2014 तक प्रतिवर्ष 171 दुर्घटनाएं होती थी और हमने घटाकर उनको 68 पर ले आए। यह हमारी उपलब्धि है। जो की पूरी तरीके से बकवास है। परसों ही 3:25 पर कानपुर में साबरमती ट्रेन की दुर्घटना हुई। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में ट्रेन हादसा हो गया। वाराणसी से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस ( ट्रेन नंबर 19168) के 20 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस ट्रेन हादसे में कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है। ट्रेन हादसे के चलते कई ट्रेनों का रद्द कर दिया गया है। साथ ही कुछ ट्रेनों का रूट डायवर्ट किया गया है।

**2014-24 के बीच हर साल 68 रेल दुर्घटनाएं, जबकि 2004-2014 के दौरान 171 दुर्घटनाएं हुई थीं: सुरक्षा उपायों पर सरकारी आंकड़े**

सोमवार को कंचनजंगा एक्सप्रेस दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि सरकार द्वारा उठाए गए सुरक्षा उपायों की वजह से परिणामी रेल दुर्घटनाओं की संख्या 171 प्रति वर्ष (2004-2014) की तुलना में घटकर 68 प्रति वर्ष (2014-2024) रह गई है।

सिलीगुड़ी के रंगापानी क्षेत्र में सुबह करीब 9 बजे 13174 कंचनजंगा एक्सप्रेस, जो अगरतला से सियालदह जा रही थी, को एक मालगाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और 40 से अधिक घायल हो गए। यह दुर्घटना उत्तर बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से सात किलोमीटर दूर हुई, जब एक्सप्रेस ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से रवाना हुई। कारण अभी भी स्पष्ट नहीं है क्योंकि जांच से पता चला है कि मालगाड़ी चालक को सभी लाल बत्तियों को पार करने की अनुमति दी गई थी क्योंकि स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली दोषपूर्ण थी, जबकि रेलवे ने दावा किया कि उसने कथित तौर पर दूरी प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया था। रेलवे ने ट्रेन यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए 2014-24 तक 1.78 लाख करोड़ रुपये खर्च किए, जो 2004-14 से 2.5 गुना अधिक है: सरकारी डेटा भारत में अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेलवे प्रणाली है। पिछले कुछ वर्षों में, भारतीय रेलवे ने रेलवे के बुनियादी ढांचे को विकसित करने, प्रणाली को आधुनिक बनाने और परिचालन दक्षता और सुरक्षा में सुधार करने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, प्रति वर्ष परिणामी रेल दुर्घटनाओं की संख्या 2000-01 में 473, 2001-02 में 415, 2002-03 में 351, 2003-04 में 325, 2004-05 और 2005-06 में 234, 2006-07 में 195, 2007-08 में 194, 2008-09 में 177, 2009-10 में 165, 2010-11 में 141, 2011-12 में 131, 2012-13 में 132 तथा 2013-14 में 118 थी। 2014-15 में यह संख्या 135, 2015-16 में 107, 2016-17 में 104, 2017-18 में 73, 2018-19 में 59, 2019-20 में 55 थी। कोविड वर्ष 2020-21 में यह संख्या 22 और 2021-22 में 35 थी। 2022-23 में यह संख्या 48 और 2023-24 में 40 थी।

**सिलीगुड़ी:** एक दुखद घटना में, अधिकारियों ने कहा कि गुरुवार को उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे कम से कम चार लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, डिब्रूगढ़ जाने वाली यात्री ट्रेन के कुछ डिब्बे मोतीगंज और झिलाही रेलवे स्टेशनों के बीच पटरी से उतर गए। बचाव कार्यों की निगरानी के लिए वरिष्ठ रेलवे और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी मौके पर हैं। यह पहली ऐसी घटना नहीं है क्योंकि इतिहास में कई ट्रेन दुर्घटनाएं हुई हैं। प्रौद्योगिकी में प्रगति और सुरक्षा उपायों में वृद्धि के बावजूद, ऐसी त्रासदियां बार-बार समाचारों में बनी रहती हैं। विज्ञापन यहां भारत में प्रमुख रेल त्रासदियों की सूची दी गई है:

**कंचनजंगा ट्रेन त्रासदी:** जून की शुरुआत में, सियालदह जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस सोमवार सुबह एक मालगाड़ी से टकरा गई, जिसके परिणामस्वरूप 10 लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक अन्य घायल हो गए। ट्रेन दुर्घटना पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में हुई। टक्कर के तुरंत बाद, बचाव कार्यों के लिए आपदा प्रबंधन दल मौके पर पहुंच गए। ट्रेन कोलकाता के सियालदह स्टेशन जा रही थी और यह दुर्घटना सिलीगुड़ी के रंगापानी क्षेत्र में हुई।

**बालासोर ट्रेन त्रासदी:** जून 2023 में, कोरोमंडल एक्सप्रेस ओडिशा के बालासोर में तीन-तरफा दुर्घटना का शिकार हुई, जिसमें 293 यात्री और 1200 से अधिक अन्य घायल हो गए। शालीमार-चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस के अलावा, ट्रेन दुर्घटना ने 2 जून को ओडिशा में बेंगलुरु-हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। यह भारत की सबसे घातक ट्रेन दुर्घटनाओं में से एक बन गई। कोरोमंडल एक्सप्रेस एक स्थिर मालगाड़ी से टकरा गई थी और इसके कुछ पटरी से उतरे डिब्बे फिर विपरीत दिशा से आ रही यशवंतपुर-हावड़ा एक्सप्रेस से टकरा गए थे।

**बिहार ट्रेन दुर्घटना:** 6 जून 1981 को बिहार में सबसे घातक रेल दुर्घटना हुई थी, जब 800 से अधिक यात्रियों को ले जा रही एक लोकल ट्रेन राज्य के मानसी और सहरसा के बीच पटरी से उतर गई और बागमती नदी में गिर गई थी। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इस घटना में 500 से 800 लोगों के मरने की आशंका थी। लोगों को बचाने का अभियान छह दिनों तक चला था। बाद में 12 जून को सरकार ने 235 यात्रियों की आधिकारिक मृत्यु की सूचना जारी की। दुर्घटना के पीछे का कारण आज तक अज्ञात है।

**पेरुमन ट्रेन टक्कर:** भारत में सबसे घातक ट्रेन दुर्घटनाओं में से एक 8 जुलाई 1988 को केरल में हुई थी, जब बेंगलुरु से तिरुवनंतपुरम जा रही आइलैंड एक्सप्रेस के 10 डिब्बे पटरी से उतर गए और अष्टमुडी झील में पेरुमन पुल से गिर गए। इस दुर्घटना में 105 यात्रियों की जान चली गई थी। दुर्घटना का कारण निश्चित नहीं है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि ट्रैक संरेखण और दोषपूर्ण पहियों के कारण यह त्रासदी हुई।

**फिरोजाबाद ट्रेन टक्कर:** 20 अगस्त, 1995 को उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के पास पुरुषोत्तम एक्सप्रेस और कालिंदी एक्सप्रेस की टक्कर में 358 लोग मारे गए थे। यह दुर्घटना लगभग 3 बजे हुई जब ट्रेन में सवार 2,200 यात्री सो रहे थे। यह दुर्घटना तब हुई जब कालिंदी एक्सप्रेस एक नीलगाय से टकरा गई और खुद पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ने पीछे से उसे टक्कर मार दी।

**गैसल ट्रेन दुर्घटना:** 2 अगस्त, 1999 को अवध असम एक्सप्रेस और ब्रह्मपुत्र मेल पश्चिम बंगाल में आमने-सामने टकरा गई, जिसके परिणामस्वरूप कम से कम 290 यात्रियों की मौत हो गई और 300 से अधिक यात्री घायल हो गए। ट्रेनों की टक्कर सिग्नलिंग त्रुटि के कारण हुई थी। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, ट्रेनें उसी ट्रैक का उपयोग कर रही थीं क्योंकि अन्य ट्रैक रखरखाव के लिए बंद थे। दोनों ट्रेनों में लगभग 2,500 यात्री यात्रा कर रहे थे।

**खन्ना रेल दुर्घटना:** 26 नवंबर 1998 को कलकत्ता जाने वाली जम्मू तवी-सियालदह एक्सप्रेस और फ्रंटियर मेल ट्रेन के बीच टक्कर होने से 212 यात्रियों की मौत हो गई थी। यह दुर्घटना जम्मू तवी-सियालदह एक्सप्रेस के फ्रंटियर मेल के छह पटरी से उतरे डिब्बों से टकराने के बाद हुई थी। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, डिब्बों के पटरी से उतरने का कारण क्षतिग्रस्त रेलवे ट्रैक था।

**बलिगोंडा ट्रेन दुर्घटना:** 29 अक्टूबर 2005 को, आंध्र प्रदेश में बलिगोंडा के पास से गुजर रही डेल्टा फास्ट पैसेंजर ट्रेन के पटरी से उतर जाने से 114 लोगों की मौत हो गई और 200 से अधिक लोग घायल हो गए, क्योंकि अचानक आई बाढ़ में नीचे का पुल बह गया था।

**ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस दुर्घटना:** 28 मई 2010 को, ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस बंगाल के मिदनापुर जिले में पटरी से उतर गई और बाद में एक मालगाड़ी से टकरा गई। इस दुखद घटना में कम से कम 148 यात्रियों की मौत हो गई। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि माओवादियों ने 46 सेंटीमीटर रेल की पटरियाँ हटा दी थीं, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई। हालाँकि, कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि बम विस्फोट के कारण यह दुर्घटना हुई।

**फतेहपुर ट्रेन दुर्घटना:** फतेहपुर में हावड़ा-कालका मेल के 15 डिब्बे पटरी से उतर जाने से लगभग 70 लोग मारे गए और 300 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। यह दुर्घटना 10 जुलाई, 2011 को 12:20 बजे हुई थी।

**आंध्र प्रदेश ट्रेन टक्कर: पिछले साल अक्टूबर में विशाखापत्तनम-**

कोरोना में सारी ट्रेनों को और पूरे रेलवे संस्थान को चौपट कर पहले तो जनता के दिमाग से तीन-चार महीने तक ट्रेनों का भूत उतारने और मजदूरों को भेजने की अपेक्षा अपने मित्र अडानी की ट्रेनों को फायदा पहुंचाने और सारे ट्रेनों को जिसके सामने नंबर शून्य से शुरू होता है सबको आईआरटीसी को अंतरित करके के बाद किराया बढ़ा आम जनता को लूटने का षड्यंत्र किया गया। बाद में बंदे भारत नाम की एक्सप्रेस ट्रेन जो चलाई गई वह पूरी तरीके से अडानी की थी। आप देखिए पिछले दो-तीन सालों में इतनी बंदे भारत ट्रेन चल रही है कहीं कोई ना तो पटरी से उतरी और ना ही कहीं पर दुर्घटनाग्रस्त हुई परंतु दूसरी अन्य ट्रेनें ही टकरा रही है एक लाइन पर तीन-तीन आ रही हैं पटरियों से उतर रही हैं। वैसे भी उनके सुरक्षित और वॉइस समय निर्धारित किए गए हैं ताकि वह जहां से गुजरे उनको अधिकतम यात्री मिले और वह ऐसी ट्रेन होने के साथ करीबी तीन गुना ज्यादा वसूलते हैं और उन ट्रेनों की तरफ लोगों को आकर्षित करने और उनमें यात्रा करने विवश करने के लिए ही जानबूझकर दुर्घटना करवाई जा रही है। हजारों लोगों की मौत के बाद जिसे वह 1% ही यात्रियों की मौत घोषित करती है। 12 -15 बोगी दुर्घटनाग्रस्त हुई और करने वाले मात्र 12 15 बीस ही होते हैं। फिर जानबूझकर यात्री रेल दुर्घटनाओं के पीछे जहां भी दुर्घटनाएं होती है वहां की जनता के साथ-साथ सबसे पहले रेलवे पुलिस फोर्स रेलवे की कर्मचारी करने वालों के आभूषण मोबाइल घड़ियां पैसा लूटने का भी षड्यंत्र करते हैं और वह भी एक बड़ा कारण बनता है विशेष सरकार स्वीकार नहीं करती परंतु होता हर जगह है हर ट्रेन दुर्घटना में मरने वालों के साथ देखिए की हर व्यक्ति दो रु.5000 जीवन डालकर चलता है एक मोबाइल जिसकी कीमत मिनिमम 10000 से लेकर दृढ़ 2 लाख तक की हो सकती है गले में चैन अंगूठी के साथ-साथ लैपटॉप बिस्तर कपड़े आखिर सब कहां गायब हो जाते हैं यह भी एक अत्यधिक ज्वलंत विचारणीय प्रश्न है। इसके बारे में ना तो सरकार बोलती है ना रेलवे के कर्मचारी अधिकारी मंत्री के साथ-साथ समाचार पत्र वाले भी कुछ नहीं छापते जबकि वह बिजनेस भी बाकायदा ठेकेदारी में करोड़ों रुपए में होता है। जिसमें रेलवे कर्मचारियों के साथ पुलिस की खुली भागीदारी होती है। देखने में यहां तक आया की पानी और अधिकारी लोग तड़पते हुए जिनका थोड़ी सी सहायता मिल जाती तो उनकी जान बचाई जा सकती थी पर उन्होंने उन्हें इसलिए शारीरिक को मानसिक सहायता नहीं दी ताकि उनका धन लैपटॉप कपड़े गहने लूटे जा सकें। भारतीय प्रताड़ना सेवा के हरामखोर जालसाज अधिकारियों को जिन्होंने पूरी जालसाजी जिसमें एवं से लेकर गिनती में एक्सेल शीट ना बनाने का खेलकर एक तरफा भुखेरा जन पार्टी की जालसाजी डकैत सरकार को जितवाकर पुनः सकता सौंप दी। बदले में जनता भूख बेरोजगारी शासकीय लूट खसोंट के तांडव को झेलने पर मजबूर है।

## आखिर मूढ़ता का परिचय दे बदनामी सरकार की करवा रही

**पेज 8 का शेष**

तब किसी भी सरकारी कार्यक्रम में उन्हें वरिष्ठतम कैबिनेट मंत्रियों से भी पहले स्थान दिया जाता था। किसी भी मीटिंग में उन्हें बेरोक टोक अपनी बात कहने का अधिकार था। उनके किसी भी पत्र का, किसी भी अनुरोध का सबसे विशेष ध्यान रखा जाता था। ऐसा कर के कॉंग्रेस सिर्फ़ उन व्यक्तियों का सम्मान नहीं करती थी। इस में उस जनता का सम्मान शामिल था, जिसने विपक्ष को वोट दिया था। इसमें उन सभी देशवासियों का सम्मान शामिल था, जो लोकतंत्र में यक़ीन करते हैं - वह लोकतंत्र जिसमें लोग सिर्फ़ सरकार को पॉवर नहीं सौंपते हैं, बल्कि जिसमें विपक्ष को सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने का अधिकार भी सौंपते हैं।आज अगर मोदी सरकार ने राहुल गांधी को पिछली क़तार में बिठाया था, तो इसमें राहुल गाँधी का असम्मान नहीं है। राहुल तो समाज के सबसे निचले पायदान पर रहने वालों के सम्मान के लिए लड़ने वाले व्यक्ति हैं, वो तो नाइंसाफ़ी के शिकार लोगों के सम्मान के लिए जूझते ही हैं।मोदी सरकार के इस फ़ैसले में उस जनता का अपमान है, जिसने राहुल गाँधी को नेता विपक्ष की ज़िम्मेदारी दी है। ये लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान है।राहुल तो लोगों के दिलों में घर बनाते जा ही रहे हैं। इस तंगदिली से सिर्फ़ मोदी सरकार का घटिया पन और आलोकतांत्रिक रवैया ही साबित होता है।

साप्ताहिक समय माया

## पूंजीपतियों के इशारे पर नाचता है, पूरा प्रशासन

# व्यापम कांड का मास्टरमाइंड विनोद भंडारी भूमाफिया, चिकित्सा और शिक्षा माफिया भी









### उच्च न्यायालय के 8:00 बजे के स्थगन के पहले ही निवास जमींदोज

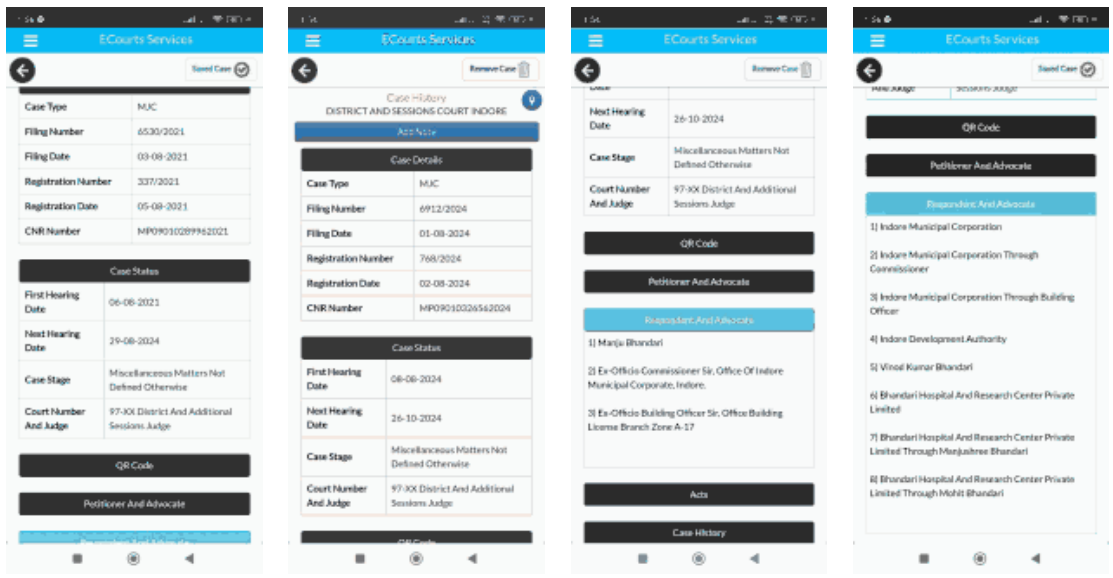

डॉक्टर विनोद भंडारी का अरविंदो हॉस्पिटल यदि उसमें जालसाजी की बात की जाए प्रवेश परीक्षा और प्रवेश देने के लिए इसने व्यापम में जो जालसाजियां की थीं और उसमें मोटी कमाई की थी उसके लिए विनोद भंडारी साढ़े तीन साल साल भोपाल की जेल में रहकर आया है। जबकि अभी तक वह प्रकरण लंबित ही है। तो उसका भवन भी जो बनाया गया है उसमें भी ना तो फायर एजेंसी मिल सकती है और ना नगर निगम उसमें पूर्णता का प्रमाण दे सकता है। उसके एक लाख वर्ग फूट से ज्यादा के लंबे चौड़े मूल भवन में अंदर प्रकाश की तो दूर ढंग से हवा भी नहीं पहुंच सकती। जो छात्र जितने भी वहां पर डेंटल, पैरामेडिकल, एमबीबीएस, एमडी, एमएस की डिग्री के जितने भी कोर्स करवाए जाते हैं। एक तो कल साड़ी पूर्ण तरीके सेउनके प्रवेश परीक्षा में विद्यार्थियों को मोटी करोडों रुपए तक की फीस में वहां उनको पढ़ने के लिए प्रवेश दिया जाता है। जबकि वहां ना तो पढ़ाने वाले अच्छे शिक्षक व्याख्याता प्राध्यापक हैं। न हीं ढंग के साधन। यथार्थ में अरविंदो हॉस्पिटल चिकित्सा शिक्षा के नाम पर केवल डिग्री बांटने की दुकान है इसके बारे में सन 2010 से लगातार लिख रहा हूं। कोरोनाकाल में आने को विद्यार्थियों की जरूरत से ज्यादा काम लेने और जोतने पर मौत भी हो चुकी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. सेत्या और कलेक्टर मनीष सिंह के साथ मिलकर अरबो रुपए के मरीजों की इलाज व रेमडिसिवर इंजेक्शन, ऑक्सीजन के व अन्य कार्यों में अरबों रुपए की बंदर बन यही कारण है कि उसके परदेशीपुरा व स्कीम नंबर 54 के हॉस्पिटल पर लीज निरस्ती के वर्षों के बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अरविंदो हॉस्पिटल के डॉक्टर विनोद भंडारी की पिछले 40 सालों में इंदौर में कितनी जमीनें पर कब्जे किए गए नियम विरुद्ध उनको बनाया गया। इसके बारे में पत्रकारों ने प्रकरण फाइल कर रखे हैं। 23/3 परदेशीपुरा में भी जहां पहले भंडारी का हॉस्पिटल था। वहां पर भी नियम विरुद्ध मंजू भंडारी के नाम से दो प्लॉट जोड़कर पीछे की बेकलेन को गायब कर अस्पताल बनाया गया था। उसका पट्टा भी 2015 में निरस्त कर दिया है। उसके बावजूद भी न हीं नगर निगम और ना ही इंदौर विकास प्राधिकरण ने उस पर कोई कार्यवाही की। यही हाल स्कीम नंबर 54में सायाजी के सामने जो भंडारी हॉस्पिटल है। उसमें भी प्लॉट नंबर 21, 22, 23 को बिना संयुक्तीकरण की अनापत्ति के रहवासी क्षेत्र में हॉस्पिटल खड़ा कर दिया गया। इसकी भी फायर एनओसी नहीं है। इसकी भी लीज 2018 में निरस्त हो गई है। पर उसको भी कलेक्टर नगर निगम और विकास प्राधिकरण ने हाथ नहीं लगाया क्योंकि मोटा पैसा मिल रहा है हरामखोरों को, जबकि दूसरों के मामले में देखते हैं आप किस प्रकार से अधिकांश औपचारिकतायें पूरी होने व सब कुछ स्पष्ट होने के बाद में भी अगर मनमानी मनचाही रकम राजस्व कलेक्टर नगर निगम विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को नहीं मिलती है। तो बसी बसाई कॉलोनियों जिन में गरीब मध्यम वर्गीयों के मकान होते हैं। तोड़फोड़ के साफ कर दिए जाते हैं।







### आखिर मूढ़ता का परिचय दे बदनामी सरकार की करवा रही

# स्वतंत्रता दिवस पर विपक्ष के नेता को पीछे बैठा अहं की संतुष्टि

140 करोड़ की आबादी के देश के की सत्ता पर अगर मूढ़ जाहिल बैठेगा तो न केवल देश का देश की जनता के साथ विधि अनुसार संचालित व्यवस्थाओं को भी अपने अहंकार की संतुष्टि के लिए बर्बाद किए जाने से अहंकार पूरा होना हो पर अपमान आवश्यक होता है आखिर राहुल गांधी को स्वतंत्रता दिवस पर पांचवी पंक्ति में बैठकर संसदीय परंपराओं का अपमान तो किया ही गया बल्कि अपनी बदनामी और मूढ़ता का भी परिचय दिया गया।

उसे उसे अहंकारी शासन की अहं की संतुष्टि हुई ना हुई। परंतु विपक्ष के नेता राहुल कीप्रशंसा अवश्य चारों तरफ देश और दुनिया में हुई। संसदीय लोकतंत्र में परम्परा बहुत साफ़ है। सदन में विपक्ष नेता का ओहदा और सम्मान अलग होता है। उनके सम्मान में लोकतंत्र का सम्मान, देश की जनता का सम्मान निहित होता है। जब भी कांग्रेस सत्ता में रही है, नेता विपक्ष को बहुत सम्मानित दर्जा दिया है। जब UPA की सरकार थी तो लाल कृष्ण आडवाणी, जसवंत सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली अलग अलग वक्त में लोक सभा और राज्य सभा में नेता विपक्ष थे।

( शेष पेज 7 पर )

साप्ताहिक
समय माया
samaymaya.com

करोड़ों किसानों मजदूरों छोटे व्यवसायियों उद्योगों, सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों ठेका संविदा कर्मियों के हितों की रक्षा व देशी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के षड्यंत्रों के विरुद्ध पिछले 25 वर्षों से संघर्षरत

साप्ताहिक समयमाया समाचार पत्र व samaymaya.com की वेबसाइट पर समाचार, शिकायतें और विज्ञापन ( प्रिंट एवं वीडियो ) के लिए संपर्क करें

मप्र के समस्त जिलों में एजेंसी देना है एवं संवाददाता नियुक्त करना है

मो. 9425125569 / 9479535569

ईमेल: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक- अजमेरा एस.पी. कुमार द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13 प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 299, अम्बेडकर नगर, इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित।
संपादकः अजमेरा एस.पी. कुमार, मो. 9425125569, भोपाल प्रतिनिधि- एस.के. भारद्वाज मो. 9425637958